आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

Ministry of Panchayati Raj
Government of India

ग्रामोदय संकल्प

श्री गिरिराज सिंह
केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
केंद्रीय राज्य मंत्री, पंचायती राज

संस्करण-14

स्वामित्व

इस संस्करण में

- स्वामित्व योजना के बारे में
- पंचायत विकास योजना के लिए जियोस्पेशियल डेटा का उपयोग
- महिला सशक्तिकरण - स्वामित्व योजना के तहत निर्मित संपत्ति कार्ड में सशक्तिकरण

श्री गिरिराज सिंह ने 'पूरे भारत में 250 मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने की परियोजना' की प्रगति की समीक्षा की

श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने 16 मार्च, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 'पूरे भारत में 250 मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने की परियोजना' की प्रगति की समीक्षा की और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR) के यंग प्रो-फेशनल्स (YFs) और 250 मॉडल ग्राम पंचायत समूहों के राज्य परियोजना समन्वयकों (SPCs) के साथ बातचीत की। इस बैठक में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार, एनआईआरडी एंड पीआर के महानिदेशक डॉ जी नरेंद्र कुमार, पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ चंद्र शेखर कुमार और पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विकास आनंद ने भाग लिया। देश के विभिन्न हिस्सों से युवाओं सहित 210 से अधिक प्रतिभागी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

इस मौके पर श्री गिरिराज सिंह ने 'पूरे भारत में 250 मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने की परियोजना' के तहत शामिल ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए मॉडल ग्राम पंचायतों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने वाले युवा साथियों को सामुदायिक भागीदारी के साथ एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहले से कहीं अधिक बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और वे स्कूल न छोड़ें। युवा साथी ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के तहत विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने इन मॉडल ग्राम पंचायतों के गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण और सभी हितधारकों के समन्वय के साथ मिशन मोड में ग्राम पंचायतों में लागू विभिन्न योजनाओं की संतृप्ति मोड को प्राप्त करने के लिए रणनीति पर काम करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने सभी YFs को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 'शिक्षा युक्त पंचायत', 'जेंडर रोजगार युक्त पंचायत', 'स्वच्छता युक्त पंचायत', 'हरित पंचायत', 'स्वस्थ पंचायत' और 'स्वस्थ पंचायत' हासिल करने के लिए समुदाय की प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा 6 ग्राम सभाओं को सुनिश्चित करना और संचालित करना है। एनआईआरडी एंड पीआर को सभी YFs की सक्रिय भागीदारी के साथ एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित करने और इस परियोजना के तहत शामिल ग्राम पंचायतों में प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए एक निगरानी डैशबोर्ड विकसित करने का सुझाव दिया गया था।

सभा की प्रमुख बातचीत भविष्य की रणनीतियों और समस्याओं को पार करने और उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करके पूरे देश में मॉडल ग्राम पंचायतों की सृजनात्मकता के प्रति चर्चा थी। शुरुआत में, NIRDPR द्वारा 'पूरे भारत में 250 मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने की परियोजना' के तहत विभिन्न पहलुओं और प्रगति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। कुछ YFs ने जमीनी स्तर पर अपने अनुभव साझा किए

विषय-सूची

मुख्य संपादक:

सुनील कुमार, आई.ए.एस.
सचिव
पंचायती राज मंत्रालय

संपादक:

डॉ. बिजय कुमार बेहरा, आई.ई.एस.
आर्थिक सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय

संपादकीय सहयोग:

आलोक पंड्या
श्रीमती कर्णिका कौशिक
आभास व्यास

03

मंत्री महोदय जी का संदेश

04

राज्य मंत्री महोदय जी का संदेश

05

सचिव महोदय का संदेश

06

भारत के माननीय प्रधान मंत्री के **स्वामित्व योजना पर संदेश**

08

स्वामित्व योजना के बारे में

13

जनभागीदारी - **भूमि सर्वेक्षण और प्रक्रियाओं की भागीदारी का एक सहभागी दृष्टिकोण**

24

ग्राम स्वराज की प्राप्ति की ओर एक कदम और **भारत को आत्मनिर्भर बनाने** की ओर

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार की ओर एक कदम - स्वामित्व योजना **09**

ग्रामीण आबादी भूमि के अधिकारों के रिकॉर्ड के निर्माण के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन मानचित्रों को जल्दी से वितरित करने के लिए एक ड्रोन आधारित फिट-फॉर-पर्पस मैपिंग समाधान **17**

पंचायत विकास योजना के लिए जियोस्पेशियल डेटा का उपयोग **19**

महिला सशक्तिकरण - **स्वामित्व योजना के तहत निर्मित संपत्ति कार्ड में सशक्तिकरण** **23**

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
MINISTER OF
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

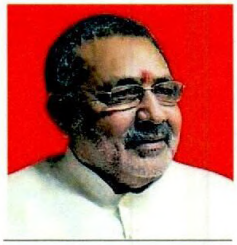

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामोदय संकल्प पत्रिका का 14 वां अंक 'स्वामित्व' योजना पर विशेष विषय के साथ प्रकाशित कर रहा है।

स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति के रिकार्ड का अधिकार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विचारों का परिणाम है और यह पहल ग्रामीण विकास में नया अध्याय लिख रही है। इस योजना के परिणाम हितधारकों के एक बड़े वर्ग को कई तरह के लाभ प्रदान कर रहे हैं, जिसमें अधिकारों का बैंकिंग योग्य रिकार्ड प्रदान करना महत्वपूर्ण है जिसका उपयोग बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, बेहतर ग्रामीण नियोजन की सुविधा के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रों का निर्माण करना, भूमि प्रशासन में सुधार, ग्राम पंचायतों में संपत्ति करों को सुव्यवस्थित करना और विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली जीआईएस अवसंरचना की स्थापना करना शामिल है।

यह हमारे लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के महत्व और प्रगति का विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार उल्लेख करते रहे हैं और इसके माध्यम से ग्रामीण भारत में समय-समय पर सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि ग्रामोदय संकल्प का यह अंक पंचायतों, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों में स्वामित्व से संबंधित जानकारी का प्रसार करेगा।

(गिरिराज सिंह)

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel.: 011-23383548, 23782373, 23782327, Fax: 011-23070309
Resi.: 27, Lodhi Estate, New Delhi, Ph.: 011-24626783, 24655677

कपिल मोरेश्वर पाटील
राज्य मंत्री
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

KAPIL MORESHWAR PATIL
MINISTER OF STATE
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मुझे प्रसन्नता है कि 'ग्रामोदय संकल्प' पत्रिका का 14वां अंक 'स्वामित्व' योजना के विषय पर प्रकाशित हो रहा है।

ग्रामीण जीवन की बुनियादी गुणवत्ता सुनिश्चित करके गांवों और पंचायतों का कायापलट करना वर्तमान समय की मांग है। वैश्विक शक्ति का दर्जा हासिल करने के भारत के दृष्टिकोण के लिए गांवों में आर्थिक प्रगति भी आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, 2020 को ग्रामीण आबादी क्षेत्र में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उसके मकान का 'अधिकार अभिलेख' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के संकल्प के साथ स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है।

स्वामित्व योजना के आगमन के माध्यम से, भूमि प्रशासन, ग्रामीण और स्थानिक योजना, भूमि मुद्रीकरण, सर्वेक्षण, बुनियादी ढांचे का निर्माण और ग्राम पंचायतों के लिए राजस्व सृजन के स्वयं के स्रोत के क्षेत्र में अवसरों का एक विशाल खजाना खुल गया है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को इस अवसर का लाभ उठाकर स्वामित्व योजना के परिणामों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि स्वामित्व पर आधारित ग्रामोदय संकल्प का यह अंक पंचायतों, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ-साथ आम जनता के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

(कपिल मोरेश्वर पाटील)

Office: Room No. 392, 'E' Wing, 3rd Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Phone: 011-23782143, 23782548, 23782518, E-mail Id: mospanchayatiraj@gmail.com, mos-mopr@gov.in
Residence: 12, Safdarjung Road, New Delhi-110011
Phone: 011-23011235, 23012116, 23012516

Generated from eOffice by ALOK PANDYA, ALOK-PANDYA(CONS), SR.CONSULTANT, MOPR on 29/05/2023 11:39 AM

सुनील कुमार, आई.ए.एस.
सचिव
Sunil Kumar, IAS
Secretary

सशक्त पंचायत सतत् विकास

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
Government of India
Ministry of Panchayati Raj
Dr. Rajendra Prasad Road,
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

संदेश

'ग्रामोदय संकल्प' पत्रिका के 14 वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह अंक **'स्वामित्व'** योजना पर केंद्रित है।

स्वामित्व योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मकान मालिक को 'रिकार्ड का अधिकार' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम बनाने के संकल्प के साथ किया गया था। इस योजना में विविध पहलुओं को सम्मिलित किया गया है, अर्थात- संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण के लिए सक्षम बनाना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना, व्यापक ग्राम स्तरीय योजना का निर्माण आदि। स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत को अत्यधिक लाभ हुआ है।

अब तक 2.36 लाख गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है, जो 3.72 लाख गांवों के कुल लक्ष्य का 63% है, और ड्रोन सर्वे का कार्य 1 राज्य एवं 4 केंद्र शासित राज्यों में पूर्ण हो चुका है। हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा के सभी आबाद गांवों के संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

ग्रामोदय संकल्प के इस अंक में स्वामित्व योजना के विभिन्न आयामों से संबधित आलेखों को समायोजित किया है, जिसमें सर्वे में ड्रोन तकनीकि का उपयोग, पंचायत विकास योजना में जियो-स्थानिक डॉटा का उपयोग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर स्वामित्व योजना का प्रभाव जैसे विषय शामिल हैं।

यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा केंद्रीय ऐजेंसियों जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, भाग लेने वाले राज्यों के राजस्व विभाग के सहयोग एवं जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। मैं इस प्रयास में सभी हितधारकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

मुझे आशा है कि यह अंक पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

29.3.23

(सुनील कुमार)

1

Generated from eOffice by ALOK PANDYA, ALOK-PANDYA(CONS), SR CONSULTANT, MOPR on 29/05/2023 12:05 PM

Tel.: 011-23389008, 23074309 Fax: 011-23389028 E-mail: secy-mopr@nic.in

भारत के माननीय प्रधान मंत्री के स्वामित्व योजना पर संदेश

माननीय प्रधान मंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। (11 अक्टूबर 2020)

"भूमि और घर का स्वामित्व देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, तो नागरिकों का विश्वास बढ़ता है"

"स्वामित्व योजना पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगी जिसके लिए पिछले 6 वर्षों से प्रयास चल रहे हैं"

- माननीय प्रधानमंत्री

माननीय प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 76वें सत्र को संबोधित किया, जहां उन्होंने स्वामित्व योजना के बारे में बात की। (25 सितंबर 2021)

"स्वामित्व रिकॉर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के सभी बड़े देशों के कई निवासियों के पास अपनी जमीन पर संपत्ति का अधिकार नहीं है। भारत में हम छह लाख गांवों में ड्रोन की मदद से मैपिंग कर रहे हैं और लोगों को उनकी जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड हासिल करने में मदद कर रहे हैं। यह डिजिटल रिकॉर्ड संपत्ति विवाद को कम करने के साथ-साथ क्रेडिट तक पहुंच यानी बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए भी फायदेमंद है।

-माननीय प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में

माननीय प्रधान मंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को ई-संपत्ति कार्ड वितरित किया। (06 अक्टूबर 2021)

"स्वामित्व योजना, ग्रामीणों को अपने व्यवसाय, कृषि के विस्तार के लिए बैंक ऋण के माध्यम से धन प्राप्त करना आसान होगा और किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा"

-माननीय प्रधानमंत्री

माननीय प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने संबोधन के दौरान प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला। (11 अक्टूबर 2022)

"उदाहरण के लिए हमारी स्वामित्व योजना को लें। हम गांवों में संपत्ति का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। इस डेटा का उपयोग करके गांवों को संपत्ति कार्ड प्राप्त हो रहे हैं।"

- माननीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संबोधन के दौरान

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में माननीय प्रधानमंत्री (18 मार्च 2023)

"स्वामित्व योजना के माध्यम से, ड्रोन तकनीक की मदद से भारत में भूमि मानचित्रण किया जा रहा है। 1 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं, इससे ग्रामीणों में डर कम हो गया था, अगर उन्होंने गांव छोड़ दिया, तो उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा"

- इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री

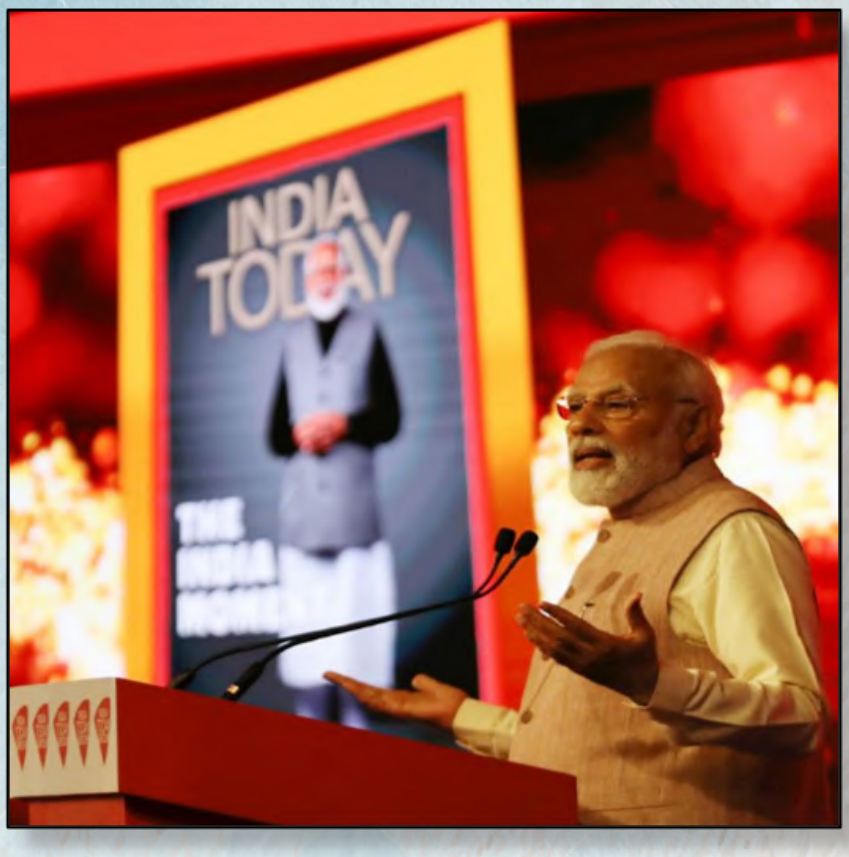

****

स्वामित्व योजना के बारे में

* स्वामित्व डिवीजन, पंचायती राज मंत्रालय

स्वामित्व योजना को माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य है कि हर ग्रामीण आवासीय क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को "स्वामित्व का दस्तावेज़" प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को संभव बनाएं। यह योजना विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करती है, जैसे संपत्ति के नकदीकरण और बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना, समग्र गांव-स्तरीय योजनाओं तैयार करना।

"स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में घरों के मालिकों को "संपत्ति के अधिकार" के रिकॉर्ड नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (CORS) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रदान किए जाते हैं। इन उच्च रिज़ॉल्यूशन और सटीक छवि आधार मानचित्रों ने इन क्षेत्रों में संपत्ति के होल्डिंग्स के सबसे टिकाऊ रिकॉर्ड का निर्माण सुविधाजनक बना दिया है। ऐसे सटीक छवि आधार मानचित्रों ने भूमि के जटिल निर्धारण को बहुत कम समय में किया जा सकता है जबकि मानचित्रण और भूमि खंडों के भौतिक माप-तोल में इस काम में लंबा समय लगता है। इसके अलावा, ये मानचित्र मापन त्रुटियों से मुक्त रहते हैं, जबकि भौतिक भूमि माप-तोल में मापन त्रुटियां मौजूद रहती हैं। ऐसे मानचित्रों ने संपत्ति विवादों की पहचान और हल करने के लिए भूमि मालिकों के लिए एक दृश्य सहायक उपकरण के रूप में और स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण के लिए अनमोल साधन हैं।"

4. योजना के उद्देश्यों को निम्नलिखित बातों की प्राप्ति के लिए है:

- ग्रामीण योजना के लिए सटीक भू-रिकॉर्ड्स का निर्माण और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करना।
- ग्रामीण भारत के नागरिकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना और उन्हें अपनी संपत्ति को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग करने की सुविधा प्रदान करना।
- संपत्ति कर का निर्धारण, जो कि सीधे ग्राम पंचायतों में जमा होगा जिन राज्यों में इसे हस्तांतरित किया गया है, अथवा राज्यों के खजाने में जमा किया जाएगा।
- सर्वेक्षण बुनियादी संरचना और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण, जिन्हें किसी भी विभाग का उपयोग कर सकता है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की बेहतर गुणवत्ता की तैयारी का समर्थन करना, जहां जीआईएस मानचित्रों का उपयोग किया जाएगा।

स्वामित्व योजना को चरणबद्ध ढंग से लागू किया गया है। पायलट चरण के सफल लागू होने और परिणामों के आधार पर, योजना को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 24 अप्रैल 2021 को लागू करने के लिए प्रवर्तन किया गया। अब तक, 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SVAMITVA योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के साथ समझौता (MoU) साइन किया है।

ड्रोन उड़ान के माध्यम से 23.03.2023 तक 2.36 लाख गांवों में सर्वे पूरा किया गया है, जो कि 3.72 लाख गांवों के कुल लक्ष्य का 63% है। दिल्ली और दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के साथ-साथ मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप के राज्यों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया गया है। राज्यों और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच निकट समन्वय के साथ हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और गोवा के सभी बसेरे गांवों के संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।

****

स्वामित्व योजना : ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार की ओर एक कदम

★ अरुण कुमार मिश्रा[1]
★ श्रीमती कर्णिका कौशिक[2]

गांव देश की आत्मा का केंद्र होते हैं। गांधीजी चाहते थे कि गांवों को नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहिए। उन्हें 'ग्राम स्वराज' की विचारधारा बहुत प्रिय थी और उन्होंने कहा था, "असली भारत केवल उपनगरों में नहीं, बल्कि सात लाख गांवों में मिलेगा। यदि गांव नष्ट हो जाएं, तो भारत भी नष्ट हो जाएगा।" गांवों और पंचायतों के रूपांतरण के माध्यम से गांवों में जीवन की मौलिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना आज की आवश्यकता है। वैश्विक शक्ति का दर्जा प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण के लिए भी गांवों में आर्थिक प्रोत्साहन महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल स्वायत्त गांवों के माध्यम से पूरा हो सकता है। विचारधारा का विकास "निचली तरफ से ऊपर बह जाएगा" गरीबों और सबसे कम सुविधाजनक लोगों के लिए मौलिक रूप से अव्यवस्थित साबित हो गई है।

इसके बजाय, हमने सीखा है कि जब हम न्यायसंगत रूप से अर्थव्यवस्था को नीचे से ऊपर मजबूत बनाने में निवेश करते हैं, तो आर्थिक विकास लंबे समय तक बेहतर होता है। 1.4 अरब लोगों के साथ भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का घर है, जिसमें 64% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आजादी के बाद से, भारत ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और ग्रामीण भारत के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और ग्रामीण क्षेत्र सरकारी नीतियों और सुधार का केंद्र रहे हैं। मार्च 2022 में जारी एनएफएचएस-5 रिपोर्ट के अनुसार - भारत के 97% घरों में बिजली है जबकि 95% ग्रामीण और 99% शहरी घरों में बिजली है। 16 मार्च 2023 तक, कुल 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.44 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन तक पहुंच है।

यह एक प्राचीन ज्ञान रहा है कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता और आर्थिक विकास के लिए मानव जाति को प्रकृति के 5 तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा: वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। सरकार ने ग्रामीण आबादी के लिए पंच तत्वों कीर समान पहुंचन सुनिश्चित करने के लिए उड़ान (उड़ेगा देश का आम नागरिक), जेजेएम (जल जीवन मिशन), पीएम-उज्ज्वला, डीआईएलआरएमपी आदि के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ी है।

भूमि हमारे ग्रह पर सबसे जटिल और महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है क्योंकि यह भोजन और आश्रय की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करती है जो जटिल नियमों द्वारा शासित होती है जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं, विभिन्न विभाग और मंत्रालय विभिन्न पहलुओं जैसे वन, कृषि, शहरी, ग्रामीण और आदिवासी भूमि को संभालते हैं। दुनिया में आर्थिक विकास के उद्देश्य से अधिकांश आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि एक आवश्यक संसाधन है। इसलिए, भूमि संसाधनों का प्रबंधन किसी भी देश की आर्थिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। किसानों को कृषि भूमि का अधिकार प्रदान करने (जमींदारी उन्मूलन), आदिवासियों (स्वायत्त जिला परिषदों) के स्वदेशी भूमि अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं, हालांकि, कुछ बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं जैसे कि अधिकार के बंधक योग्य रिकॉर्ड की कमी पूर्व सर्वेक्षण रिकॉर्ड की अनुपलब्धता, या गैर-मान्यता प्राप्त भूमि अधिकारों के कारण आबादी वाली भूमि (आबादी क्षेत्र)। ग्रामीण भारत के बसे हुए क्षेत्र (आबादी भूमि) बड़े पैमाने पर किसी भी सुधार के दायरे में रहे। कुछ राज्यों ने आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था और वस्तुतः आबादी क्षेत्रों का कोई पूर्व मानचित्र मौजूद नहीं है। भारत के 6.6 लाख गांवों में आबादी भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए कोई समन्वित प्रयास नहीं किया गया था। इसके कारण अबादी क्षेत्र में ग्रामीण आबादी के लोगों के लिए कई समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसे कि उनकी संपत्ति पर ऋण लेने में असमर्थता, सटीक भूमि रिकॉर्ड की कमी, ऋण

★ उप सचिव, स्वामित्व प्रभाग, पंचायती राज मंत्रालय
★ कंसल्टेंट, स्वामित्व, पंचायती राज मंत्रालय

लेने के लिए प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों की बजाय मनी लेंडर्स की ओर रुख करना, अनुबंधित योजना या अनियोजित ग्रामों का विकास के कारण, अबादी क्षेत्रों के किसी भी मानचित्र की अनुपस्थिति के कारण।

ग्रामीण क्षेत्रों के इन निवासियों के पास गैर-संस्थागत ऋणदाताओं से ऋण लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था जो उनसे अत्यधिक ब्याज दरें वसूल सकते हैं; अनभिज्ञ ग्रामीण आबादी के बीच जागरूकता की कमी उन्हें बढ़ते कर्ज के जाल में फंसा देती है, जिससे वे साहूकारों की दया पर निर्भर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब संस्थागत ऋण तक पहुंच की बात आती है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित घरेलू संपत्ति और ऋणग्रस्तता सर्वेक्षण 2013 के अनुसार, लगभग 20% ग्रामीण परिवारों ने गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के साथ बकाया ऋण की सूचना दी है। जबकि शहरी भारत के लिए यही संख्या 10% है। वास्तव में, भारत में एक औसत परिवार अपनी कुल संपत्ति का लगभग 77% अचल संपत्ति में रखता है (जिसमें आवासीय भवन, कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतें, मनोरंजक सुविधाओं जैसे निर्माण और ग्रामीण और शहरी भूमि शामिल हैं) . भारत में ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में अधिकारों के रिकॉर्ड (आरओआर) की कमी के परिणामस्वरूप भूमि प्रशासन का निम्न स्तर, संपत्तियों का अनुमानित स्वामित्व, लंबे समय से लंबित संपत्ति से संबंधित विवाद और ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित भूमि बाजार होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अबादी वाले क्षेत्रों के रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (रोआर) की कमी और सर्वेक्षण की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण घरेलू स्वामियों को संपत्ति कार्ड के रूप में आरोहण करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे स्वामित्व (ग्रामों के आबादी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ गांवों के सर्वेक्षण) योजना की संकल्पना हुई। पारंपरिक श्रृंखला-आधारित, क्रॉस-स्टाफ और थियोडोलाइट-आधारित सर्वेक्षण तकनीकों में आम तौर पर उपकरण और जमीन के बीच लाइन-ऑफ़-विज़न और सर्वेक्षण किए जाने वाले पूरे क्षेत्र के स्पष्ट दृश्य की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, संपत्ति पार्सल का सीमांकन करने के लिए सर्वेक्षक को उपकरणों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है। भूमि सर्वेक्षण की यह पद्धति श्रमसाध्य, समय लेने वाली, महंगी और मानवीय तथा उपकरण संबंधी त्रुटियों से ग्रस्त है।

भारत के गांवों में हमारे सुशासन प्रयासों के मूल में लोगों के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाना है। इसका एक उदाहरण स्वामित्व है जिसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं: श्री नरेंद्र मोदी

SVAMITVA योजना बहुत कम समय में बड़ी आबादी क्षेत्रों का सटीक सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन और CORS नेटवर्क (लगातार संचालित संदर्भ स्टेशन) के संयोजन का उपयोग करती है। ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से उत्पन्न 1:500 पैमाने के भू-टैग किए गए नक्शे लागत के एक अंश पर बनाए जाते हैं और बहुत उच्च सटीकता यानी 3-5 सेमी के होते हैं, जो पारंपरिक पद्धति प्रदान नहीं करती है। SVAMITVA योजना दुनिया में ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है।

"स्वामित्व योजना के लिए गाँवों के निवासियों में बहुत उत्साह और उत्सुकता है। चुन्ना मार्किंग चरण के दौरान जनभागीदारी के माध्यम से रहवासियों ने अपनी जमीन की हकीकत जानी। यह योजना गांव के निवासियों के बीच काफी चर्चा में रही है और कुछ लाभार्थियों ने होमस्टे के निर्माण के लिए बैंक ऋण भी लिया है। निवासी प्राप्त संपत्ति कार्ड से काफी खुश हैं"- श्रीमती सुमन गोदियाल, ग्राम प्रधान, गोदा गांव, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड

स्वामित्व योजना का लक्ष्य गांव के उन परिवारों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना है जिनके पास बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घर हैं और संपत्ति के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना जो राज्य के राजस्व या पंचायती राज अधिनियमों द्वारा समर्थित हैं। यह क्रेडिट और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। स्वामित्व योजना की प्रक्रिया को ग्राम सभा के रूप में जनभागीदारी (लोगों की भागीदारी) सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो योजना के बारे में ग्रामीण आबादी को संवेदनशील बनाने, संपत्तियों के सीमांकन के लिए आयोजित की जाती है। चूना लाइनों का उपयोग गांव के संपत्ति मालिकों की उपस्थिति में किया जाता है, और यदि कोई विवाद ग्राम पंचायत में सौहार्दपूर्वक सुलझाया जाता है।

"मैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत 2,90,000 रुपये का ऋण प्राप्त करने में सक्षम था। - श्री पवन, हरदा (मध्य प्रदेश)

भू-संदर्भित उच्च रिज़ॉल्यूशन मानचित्र ग्राम पंचायत को प्रत्येक गाँव में संपत्तियों की सटीक संख्या के साथ-साथ उनके आयामों के साथ अपने संपत्ति रजिस्टरों को अद्यतन करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह उन ग्राम पंचायतों में संपत्ति कर निर्धारण और संग्रह को सुव्यवस्थित करने का एक तरीका प्रदान करता है जहां इसे हस्तांतरित किया जाता है, इस प्रकार राजस्व के अपने स्रोतों का निर्माण होता है जिसका विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए लाभकारी उपयोग किया जा सकता है।

"डिजिटाइज्ड नक्शों के माध्यम से, ग्राम पंचायत खाली जमीन के स्वामित्व की पहचान के परिणामस्वरूप संपत्ति कर संग्रह में 16% की वृद्धि करने में सक्षम थी" - श्रीविलास बडाधे, सचिव, वालुज ग्राम पंचायत, पुणे, महाराष्ट्र

संक्षेप में, योजना का लक्ष्य है:

- सही भूमि अभिलेखों के माध्यम से परिवार को संपत्ति का अधिकार प्रदान होंगे
- संपत्ति के मालिकों द्वारा मुख्यधारा के वित्तीय संस्थानों से ऋण आवेदन करने के लिए रास्ते खुलेंगे
- संपत्ति संबंधी विवाद कम होंगे
- स्पष्ट स्वामित्व, सटीक आकार निर्धारण और पारदर्शी भूमि शीर्षक के साथ, SVAMITVA राज्यों को संपत्ति कर निर्धारण और संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की एक अभूतपूर्व संभावना प्रदान करता है, जो पंचायत को स्थानीय उपयोग/विकास कार्य के लिए उपलब्ध होगा। इससे ग्राम पंचायतों को वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी।
- बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी में सहायता के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड और जीआईएस मानचित्र बनाएं जा सकेंगे
- पंचायतों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को बढ़ेगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगी

राम प्रसाद, जगत राम और शांति प्रसाद के बीच विवाद का निपटारा। विवाद के निपटारे के बाद, संपत्ति पर पशु फार्म का निर्माण किया गया जिससे निवासियों के बीच सामाजिक सद्भाव बढ़ा। साथ ही, राज राजेश्वरी मंदिर का स्वामित्व अधिकार ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया, जिसके कारण ग्राम पंचायत में सामाजिक समावेशन के लिए मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। - धनोल्टी तालुका, जिला टिहरी (गढ़वाल)

SVAMITVA योजना की शानदार सफलता

15 मार्च 2023 तक 72,997 गांवों के लिए 1.22 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। 2.34 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है. योजना को हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, अंडमान-निकोबार द्वीप और पुडुचेरी में संतृप्त किया गया है।

अपने मिशन के माध्यम से **'जन सामान्य की सरकार'** बनने के लक्ष्य के साथ, यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर नेतृत्व के समर्थन को प्राप्त कर चुकी है, जहां माननीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न आयोजनों में और राज्य के मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्य स्तरीय आयोजनों के दौरान लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड सीधे हस्तांतरित किए हैं।

1. योजना के पहले मील के पत्थर के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री ने छह पायलट चरण राज्यों (महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश) के 763 गांवों के लगभग 1 लाख संपत्ति मालिकों को 11 अक्टूबर 2023 को संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया।

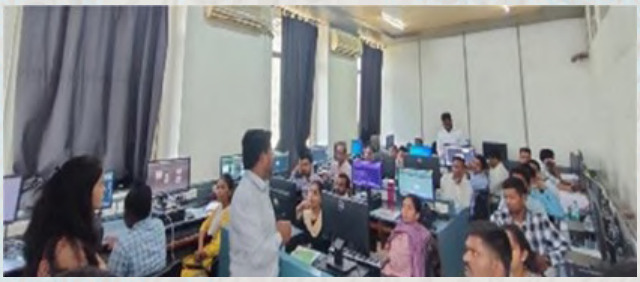

24 अप्रैल 2021 को, माननीय प्रधान मंत्री ने हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के 5002 गांवों के लगभग 4.09 लाख संपत्ति मालिकों के लिए योजना का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन और वितरण शुरू किया

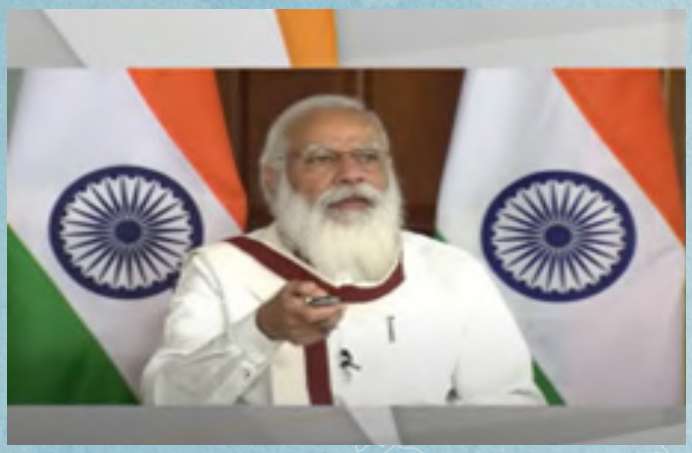

* 6 अक्टूबर 2021 को माननीय प्रधान मंत्री ने मध्य प्रदेश के 3000 गांवों में 1.70 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए।

* 23 दिसंबर 2021 को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर भूमि संबंधी विवादों को कम करने के निरंतर प्रयास में, माननीय प्रधान मंत्री ने वाराणसी में उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक लाभार्थियों को घरौनी वितरित की।

* 24 अप्रैल 2022 को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर, माननीय प्रधान मंत्री ने पल्ली जीपी, सांबा जिला, जम्मू और कश्मीर में संपत्ति कार्ड वितरित किए।

* उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 23 जून 2022 को 75 जिलों में 10.81 लाख घरौनी वितरित कीं।

****

जन-भागीदारी
भूमि सर्वेक्षण के प्रति सहभागी दृष्टिकोण

★ गर्वित त्रिवेदी

स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सहयोगात्मक प्रयास है। योजना को लागू करने में शामिल गतिविधियों को मोटे तौर पर पूर्व-सर्वेक्षण, सर्वेक्षण और सर्वेक्षण के बाद की गतिविधियों में विभाजित किया गया है।

i. स्वामित्व योजना के कार्यान्वियन के लिए प्रारंभिक गतिविधियां

इस योजना के लाभ क्रांतिकारी हैं और स्वामित्व योजना के लाभों/परिणामों को साकार करने के लिए, हितधारकों के साथ समन्वय में पूर्व-सर्वेक्षण से संबंधित गतिविधियों का परिश्रमपूर्वक पालन किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक हितधारक की भागीदारी महत्वपूर्ण है और गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ड्रोन सर्वेक्षण गतिविधियाँ करता है और राज्य राज्य में योजना के कार्यान्वियन के लिए जिम्मेदार है, SVAMITVA योजना के कार्यान्वियन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद, राज्यों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग को योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कुछ गतिविधियां करने की आवश्यकता है। सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीति का उद्देश्य योजना के तहत उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना और जानकारी का प्रसार करना और ग्रामीण आबादी को उन तक पहुंचने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करना है। इसमें गांव के निवासियों को योजना के बारे में जागरूक करने के लिए पंचायतों द्वारा आईईसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

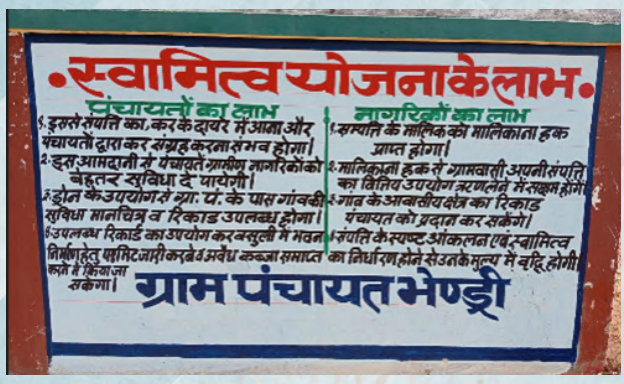

छत्तीसगढ़ में योजना के लाभ की जानकारी देती वॉल पेंटिंग

पंचायतें योजना पर लघु फिल्में/वीडियो प्रदर्शित करते हुए जागरूकता और गतिशीलता के लिए एक ग्राम सभा का आयोजन कर सकती हैं। पंचायतों द्वारा दीवार पेंटिंग, लघु नाटक या नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जा सकता है। पंचायतें व्यापक पहुंच के लिए सूचना प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का भी उपयोग करेंगी। राज्य को भी अपने अधिनियम/नियमों में स्वामित्व कार्यान्वियन को शामिल करने या प्रावधान करने की आवश्यकता है।

ग्राम सभा

इस योजना का उद्देश्य आबादी क्षेत्र के निवासियों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार करना है। इसे ध्यान में रखते हुए, एक जिले के भीतर, राज्य द्वारा आबादी गांवों की संख्या अधिसूचित की जानी है जिनका योजना के तहत सर्वेक्षण किया जाएगा। पंचायतों को आबादी की सीमाओं का चयन करना भी आवश्यक है। सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी राजस्व अधिकारियों को चूना मार्किंग, ड्रोन सर्वेक्षण के बाद बनने वाले नक्शों का सत्यापन आदि जैसी सर्वेक्षण प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। स्वामित्व योजना का अन्य घटक भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राज्यों में CORS की स्थापना है। राज्य को भारतीय सर्वेक्षण विभाग को साइटें उपलब्ध करानी होंगी, यह अनुशंसा की जाती है कि पहचानी गई साइट सक्षम बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सरकारी परिसर में होनी चाहिए।

★ कंसल्टेंट, स्वामित्व, पंचायती राज मंत्रालय

"भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तहसील स्तर के अधिकारियों, ग्राम पंचायतों और राज्य के राजस्व अधिकारियों के बीच सहयोग के परिणामस्वरूप; ड्रोन टीम ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 11 गांवों को कवर किया" - संखेड़ा तालुका, छोटा उदेपुर जिला, गुजरात

ii. ड्रोन आधारित सर्वेक्षण प्रक्रिया

सर्वेक्षण-पूर्व गतिविधियों को पूरा करने के बाद, राज्य और भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोनों ड्रोन सर्वेक्षण में शामिल हो गए हैं। ड्रोन उड़ान शुरू करने से पहले, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट (जीसीपी) स्थापित करना आवश्यक है जो हवाई छवियों को कैप्चर करने के लिए ड्रोन पथ को परिभाषित करेगा। एक बार जब छवियां कैप्चर कर ली जाती हैं और ऑर्थो-रेक्टिफाइड इमेज (ओआरआई) उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसे मानचित्र और उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्थानिक डेटा के निर्माण के लिए आगे संसाधित किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग फीचर निष्कर्षण के लिए भी जिम्मेदार है जिसमें ग्रामीण आवासीय संपत्तियों का सटीक मानचित्रण और सीमांकन करने के लिए डेटा का संग्रह, छवि अधिग्रहण, छवि विभाजन और छवि प्रसंस्करण शामिल है। फीचर निष्कर्षण के बाद, गांव के मानचित्र में उल्लिखित विवरणों के सत्यापन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पहला मसौदा मानचित्र राज्य को प्रस्तुत किया जाता है।

Setting up of Ground Control Points

iii. सर्वेक्षण के बाद शामिल गतिविधियां

सर्वेक्षण गतिविधियों के बाद, राज्य को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए पहले ड्राफ्ट मानचित्र का जमीनी सत्यापन करना होगा। फीचर निष्कर्षण प्रक्रिया के माध्यम से बनाए गए संपत्ति मानचित्रों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड सत्यापन एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें जमीन-आधारित सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करके संपत्ति की सीमाओं और अन्य विशेषताओं का भौतिक सत्यापन शामिल है।

Abandoned land identified under the scheme

अधिनियम के अंतर्गत, मानचित्र में किसी भी विचलन के मामले में आपत्ति के लिए दिनों की संख्या राज्य से राज्य भिन्न हो सकती है। स्वामित्व के न्यायिकरण के लिए जांच/आपत्ति प्रक्रिया ग्राम सभा, भूमि मालिकों की सहायता से और मौजूद दस्तावेजों की समीक्षा के साथ जांच की जाती है और संपत्ति मालिकों से प्राप्त किसी भी आपत्ति को जन भागीदारी के माध्यम से

हल की जाती है। इसके बाद, ग्रामीण घरेलू स्वामियों को संपत्ति कार्डों की मुद्रण और वितरण राज्य के द्वारा किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण सर्वेक्षण विभाग कर्मचारियों को नियमित अपडेट और मानचित्र के उपयोग के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी प्रदान करेगा।.

शामिल हितधारक

योजना के कार्यान्वियन को व्यवस्थित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य राजस्व और पंचायती राज विभाग और ग्राम पंचायतों के लिए योजना के ढांचे में स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित की गई हैं।

स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय नोडल विभाग है। यह केंद्रीय स्तर पर योजना की फंडिंग और निगरानी का प्रबंधन करता है। मंत्रालय सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना और ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को धन मुहैया कराता है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना और आईईसी गतिविधियों के लिए राज्यों को धनराशि जारी की जाती है। स्वामित्व निगरानी डैशबोर्ड और स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के विकास के लिए एनआईसी को धनराशि जारी की जाती है।

सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण गतिविधियों की सर्वेक्षण योजना, निष्पादन और निगरानी और उच्च-रिज़ॉल्यूशन 1:500 पैमाने की छवियों और स्थानिक डेटा के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग राज्य के ग्रामीण आबादी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करके हवाई तस्वीरें खींचेगा। ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण के बाद उत्पन्न छवियों की पोस्ट-प्रोसेसिंग भी भारतीय सर्वेक्षण द्वारा की जाएगी। एक बार ओआरआई संसाधित हो जाने के बाद, एसओआई पहला ड्राफ्ट मैप तैयार करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग और फीचर निष्कर्षण पर काम करेगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग योजना के तहत सतत संचालन संदर्भ स्टेशनों (सीओआरएस) की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश संपत्ति कार्ड के प्रारूप को उचित अधिकार और वैधता प्रदान करने के लिए भूमि राजस्व संहिता और/या किसी अन्य प्रशासनिक दस्तावेज़ में उचित संशोधन करते हैं। राज्य राजस्व विभाग राज्य राजस्व अधिनियम में ग्रामीण बसे हुए क्षेत्रों के सीमांकन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण करने के लिए की जा सकने वाली गतिविधियों की सीमा की भी जाँच करता है। राज्यों को क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने से पहले मालिकों और ग्राम पंचायत के साथ चुन्ना लाइनों के साथ संपत्ति की सीमाओं को चिह्नित करना होगा। विभाग आवश्यकता पड़ने पर योजना के कार्यान्वियन के लिए गांवों को नोटिस जारी करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ- साथ क्षेत्रीय सर्वेक्षण-संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना चाहिए ताकि समझ में कोई अंतर न रहे। एक बार जब भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पहला मसौदा नक्शा राज्य को सौंप दिया जाता है, तो अन्य ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ-साथ राज्य द्वारा भूमि पार्सल मानचित्रों का जमीनी सत्यापन और सत्यापन किया जाना चाहिए। संपत्ति मालिकों से सर्वेक्षण के बाद की आपत्तियां प्राप्त करने के बाद राज्य को राजस्व मानचित्रों को अंतिम रूप देना चाहिए और संपत्ति कार्डों की तैयारी और वितरण की दिशा में काम करना चाहिए ताकि संपत्ति मालिक योजना का लाभ उठा सकें।

राज्य पंचायती राज विभाग सर्वेक्षण की अनुसूची और फीचर-नक्शे गए मानचित्रों के सर्वेक्षण के बाद सुधार की जानकारी देने के लिए ग्राम सभा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। यह ग्रामीणों को परियोजना कार्य और आईईसी आदि के लिए आरजीएसए निधि का लाभ उठाने के इच्छित लाभों के बारे में जागरूक करने में सहायता प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। उन्हें GPs के माध्यम से संपत्ति (टैक्स) रजिस्टर भी तैयार और अपडेट करना है।

स्वामित्व योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सर्वेक्षण के बारे में गांव के निवासियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। ग्राम पंचायत को सर्वेक्षण संबंधी गतिविधियों को समय पर पूरा करने में पंचायती राज विभाग और राज्य राजस्व विभाग की मदद करनी चाहिए।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी जब गांव में सर्वेक्षण संबंधी गतिविधियां कर रहे हों तो ग्राम पंचायत के एक अधिकारी को भी उनके साथ रहना चाहिए। अंतरिम मानचित्र/अभिलेख तैयार करने के लिए पंचायतों को मौजूदा जीपी संपत्ति (कर) रजिस्टरों को डिजिटाइज करना होगा, जहां भी लागू हो, सर्वे ऑफ इंडिया और जांच अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। सर्वेक्षण के संचालन के लिए जमीनी स्तर की गतिविधियों का समन्वय। पंचायत, जहां भी लागू हो, ग्राम पंचायत के संपत्ति कर और संपत्ति रजिस्टर को अद्यतन करने और संपत्ति मालिकों से सर्वेक्षण के बाद प्राप्त आपत्तियों के समाधान में मदद करने के लिए भी जिम्मेदार है। आपत्तियाँ मालिक के नाम, संपत्ति की सीमाओं आदि में सुधार से संबंधित हो सकती हैं।

****

कर्नाटक के रामनगर में संपत्ति कार्ड वितरण

****

ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के लिए अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन मानचित्रों को शीघ्रता से वितरित करने के लिए एक ड्रोन आधारित उद्देश्यानुसार निर्मित मैपिंग समाधान

★ प्रदीप सिंह

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई), राष्ट्रीय भू-स्थानिक एजेंसी राष्ट्रीय स्थलाकृतिक टेम्पलेट की तैयारी, अद्यतनीकरण और रखरखाव, कार्यात्मक सीमाओं, मानकीकृत भौगोलिक स्थान के नाम, एकीकृत जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बीच राष्ट्रीय भूगर्भिक संदर्भ फ्रेम (एनजीआरएफ) के रखरखाव और उन्नयन के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि भू-स्थानिक इंटरफ़ेस (यूजीआई), राष्ट्रीय भू-स्थानिक डेटा रजिस्ट्री (एनजीडीआर), भू-स्थानिक क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास आदि। भारत में वैज्ञानिक सर्वेक्षण 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ शुरू हुए। भारतीय सर्वेक्षण दो शताब्दियों से अधिक समय से विशाल और विविध क्षेत्रों के सर्वेक्षण और मानचित्रण में लगा हुआ है और कागजी मानचित्रों से लेकर डिजिटल मानचित्रों और फिर उद्यम जीआईएस प्रणालियों तक विभिन्न चरणों से गुजर चुका है।

वर्तमान में, SOI भू-स्थानिक डेटा के अधिग्रहण, प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए सभी नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर रहा है - जैसे कि लगातार संचालित संदर्भ स्टेशन (CORS) नेटवर्क, उच्च रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, विमान आधारित हवाई फोटोग्राफी - LiDAR और ऑप्टिकल सेंसर, ड्रोन आधारित मैपिंग आदि का उपयोग करना। देश की ऊंचाई प्रणाली को भी फिर से परिभाषित किया जा रहा है - जिसके लिए उच्च परिशुद्धता समतलन और गुरुत्वाकर्षण अवलोकन किए जा रहे हैं। जब भारत में वैज्ञानिक सर्वेक्षण और माप की बात आती है तो एक संस्था के रूप में SOI हमेशा उल्लेखनीय रहा है - महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण और 19वीं सदी में सबसे ऊंची चोटी की माप, 20वीं सदी में 1:50K पैमाने पर पूरे देश का मानचित्रण और जियोडेटिक का आधुनिकीकरण। 21वीं सदी में संदर्भ फ़्रेम। 1905 तक एसओआई त्रिकोणमितीय, स्थलाकृतिक और राजस्व सर्वेक्षण कर रहा था। 1905 में, राजस्व सर्वेक्षण को राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत में, अधिकांश राज्यों में बस्तियों (आबादी क्षेत्रों) का शायद ही कभी मानचित्रण किया गया है और इन क्षेत्रों के लिए अधिकारों का कोई रिकॉर्ड (आरओआर) मौजूद नहीं है। मानचित्रों और आरओआर की गैर-मौजूदगी ने इन क्षेत्रों को औपचारिक भूमि प्रशासन प्रणालियों से बाहर कर दिया है। भारत में लगभग 6,62,000 से अधिक ग्रामीण गांवों में आबादी क्षेत्रों का मानचित्रण करने के लिए, बेहतर रिज़ॉल्यूशन पर ड्रोन द्वारा प्राप्त छवियों का उपयोग करके बहुत उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले मानचित्र/डेटा तैयार करने के लिए वर्ष 2020 में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम (स्वामित्व योजना) शुरू किया गया है। 5 सेमी. उच्च रिज़ॉल्यूशन जीआईएस और मानचित्र तैयार किए गए जिसके आधार पर ग्रामीण नागरिकों को आरओआर जारी किए जा रहे हैं। SOI स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन में पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) का प्रौद्योगिकी भागीदार है।

ड्रोन आधारित मानचित्रण के लिए व्यापक कार्य-चरणों में शामिल हैं;

1. ड्रोन तैनाती की योजना बनाने के लिए स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा ड्रोन आधारित मानचित्रण के लिए गांवों की अग्रिम अधिसूचना।
2. उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली और प्रौद्योगिकी के बारे में गांव के नागरिकों को शिक्षित करना - यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि एक भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया जाए और ग्रामीण आबादी कार्यक्रम, सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी, कार्यप्रणाली और परिणाम के बारे में जागरूक हों।
3. जमीन पर संपत्तियों के पार्सल का सीमांकन और ड्रोन उड़ान - ड्रोन उड़ान से पहले संपत्तियों के पार्सल का सीमांकन छवियों में चिह्नित पार्सल को कैप्चर करने में सक्षम बनाता है और इसलिए पार्सल मानचित्र निर्माण के दौरान ड्रोन उड़ान के बाद की गतिविधियों में प्रयास कम हो जाता है।
4. ड्रोन डेटा प्रोसेसिंग और जीआईएस/मानचित्रण उत्पादन – ड्रोन डेटा प्रोसेसिंग का कार्य SOI कार्यालयों में स्थानीय उच्च स्तरीय मशीनों में हो रहा है, जिनमें ड्रोन डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर स्थापित है। क्लाउड आधारित प्रोसेसिंग का भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन साइट से छवि डेटा को क्लाउड पर भेजना बैंडविड्थ सीमाओं के कारण चुनौतीपूर्ण हो रहा है।

★ उप महासर्वेक्षक, नोडल अधिकारी, स्वामित्व

5.ग्राउंड ट्रूथिंग/गुणसूत्र संग्रह – पार्सल मानचित्र एक बार तैयार होने के बाद, इसे ग्राउंड ट्रूथिंग/मान्यता प्राप्ति और गुणसूत्र डेटा संग्रह के लिए भेजा जाता है। फिर सुधारित जीआईएस/मानचित्र और गुणसूत्रों के साथ यह नया मानचित्र संबंधित विभाग को प्रदान किया जाता है, जिससे संपत्ति मालिकों के आपत्तियों का पता लगाने और समस्याओं को हल करने के लिए जांच प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। अंतिम जीआईएस/मानचित्र उत्पादन – अनिवार्य जांच प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद पार्सल मानचित्र तय किया जाता है और राइट्स ऑफ राइट्स जारी किए जाते हैं।.

'ड्रोन आधारित मानचित्रण के लिए गांव की पहचान' के चरण से लेकर 'जीआईएस और मानचित्र तैयार करने' तक की संपूर्ण कार्यप्रवाह समय सीमा 20 दिनों से 35 दिनों तक भिन्न होती है। स्वचालित या अर्ध-स्वचालित निर्बाध वर्कफ़्लो समय सीमा को लगभग 15 दिनों तक कम कर सकता है। मार्च, 2023 तक देश भर में अलग-अलग इलाकों में फैले 2,30,000 से अधिक गांवों की ड्रोन तस्वीरें हासिल की जा चुकी हैं। विभिन्न श्रेणियों के लगभग 200 से अधिक ड्रोन - वीटीओएल के साथ फिक्स्ड विंग, क्वाडकॉप्टर इमेज कैप्चरिंग के लिए क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित गांवों के आधार पर ड्रोन तैनात किए जाते हैं। इस प्रयास में एसओआई ने ड्रोन का उपयोग करके 5 सेमी से बेहतर रिज़ॉल्यूशन पर 10,000,00,00 से अधिक तस्वीरें कैप्चर की हैं।

भारत में ड्रोन नियम: ड्रोन के विशाल बेड़े के संचालन के लिए चरम समय में एक अनुकूल ड्रोन नीति की आवश्यकता थी, छवि डेटा कैप्चरिंग के लिए राज्यों भर में लगभग 300 से अधिक ड्रोन तैनात किए गए थे। नागरिक उड्डयन के लिए भारतीय सरकारी नियामक निकाय, महानिदेशक नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) ने ड्रोन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। ये नियम व्यापक और स्पष्ट हैं और योजना के कार्यान्वयन में प्रभावी रहे हैं

ड्रोन के बारे में: ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन - यूवीएस (मानव रहित वाहन प्रणाली) अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार, एक मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) बिना किसी मानव पायलट के संचालित करने के लिए एक सामान्य विमान डिजाइन है। ड्रोन तकनीक को शुरुआत में सैन्य या रक्षा अनुप्रयोगों जैसे निगरानी, निरीक्षण, रेकी आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। हाल ही में, बहुत उच्च रिज़ॉल्यूशन की हवाई तस्वीरें प्राप्त करने के लिए ड्रोन प्लेटफ़ॉर्म आम हो गया है। उच्च अंत कंप्यूटिंग मशीनों का उपयोग करने वाली स्वचालित फोटोग्रामिट्रिक प्रक्रियाओं ने बड़े पैमाने पर स्थलाकृतिक मानचित्र के लिए ड्रोन प्लेटफ़ॉर्म की क्षमता का प्रदर्शन किया है।

स्वामित्व योजना के लिए, एसओआई ने विभिन्न श्रेणियों के अपने ड्रोन खरीदे हैं - वीटीओएल, क्वाडकॉप्टर के साथ फिक्स्ड विंग। एसओआई की अपनी ड्रोन इन्वेंट्री के अलावा, निजी भारतीय फर्मों से ड्रोन टीमों को किराए पर लेने और फर्मों के पैनलबद्ध करने के माध्यम से ड्रोन सेवाएं भी तैनात की गई हैं। एसओआई अब तक इस योजना को लागू करने में सफल रही है और मार्च, 2024 तक लक्षित गांवों में ड्रोन उड़ान को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेगी।

****

पंचायत विकास योजना के लिए भू-स्थानिक डेटा का उपयोग

★ सुशांत सुधीर

भारत ने पिछले कुछ दशकों के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ उल्लेखनीय आर्थिक विकास का अनुभव किया है। हालांकि, इस आर्थिक विकास को बड़े पैमाने पर बड़े मेट्रो शहरों और देश भर में फैले कुछ शहरी-औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा प्रेरित किया गया है। कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों को अभी भी बेरोजगारी, खराब बुनियादी ढांचे, कम प्रति व्यक्ति आय और परिणामी निम्न जीवन स्तर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा, अधिकांश ग्रामीण बस्तियां जो प्रमुख रूप से अव्यवस्थित और अनियोजित हैं। विकास; गैर-अनुरूप भूमि उपयोग; भूमि का कृषि से अन्य भूमि उपयोग आदि में अनियोजित परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय गिरावट और जीवन की खराब गुणवत्ता होती है।

गांवों में भी तेजी से अनियोजित और अनधिकृत विकास देखा जा रहा है, विशेष रूप से उपनगरीय क्षेत्रों में, गाँव के विस्तारित आबादी (आवासीय) क्षेत्र में और राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पंचायतों में। यदि उन्हें शहरी क्षेत्र की सीमा में या विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में पेश किया जाता है, तो उन्हें बाद में मास्टर प्लानिंग जैसे शहरी स्थानिक नियोजन हस्तक्षेपों की मदद से नियमित और रेट्रोफिट करना होगा। गांवों के अनियोजित आबादी क्षेत्र (जिन्हें लाल डोरा कहा जाता है) जो पहले से ही बसे हुए हैं, आगे के विकास के लिए बहुत जटिल हो जाते हैं। गांवों के आबादी क्षेत्रों में सटीक संपत्ति रिकॉर्ड की कमी इस असंगठित विकास के प्राथमिक कारणों में से एक है और इसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय योजना हस्तक्षेप के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।

पंचायतें जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के तीसरे स्तर का गठन करती हैं और उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 जी द्वारा विशेष रूप से अनिवार्य किया गया है। हालांकि, अपनी वर्तमान व्यवस्था में, पंचायतों के पास ऐसा प्रयास करने के लिए न तो साधन हैं और न ही क्षमता। स्वामित्व योजना की शुरुआत के साथ आबादी क्षेत्रों के संपत्ति पार्सल रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और जीआईएस की मदद से उच्च रिज़ॉल्यूशन मानचित्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है और इससे प्राप्त डेटा का उपयोग स्थानिक योजना और ओएसआर के संवर्द्धन के लिए किया जा सकता है, जिससे पंचायतें सशक्त होंगी।

> *भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी समावेशन और प्रगति को बढ़ावा दे रही है। हमारी SVAMITVA (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना को लें, हम गांवों में संपत्तियों के मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। दशकों में पहली बार, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास स्वामित्व का स्पष्ट प्रमाण है- श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधान मंत्री*

भारत में परिभाषित स्थानिक योजना प्रणाली ढांचा, विभिन्न स्तरों पर प्रमुख रूप से स्थानिक योजना पहलुओं का गठन करता है और इसे कानूनी समर्थन प्राप्त है जिस पर यह कायम है (वैधानिक प्रावधान)। जिन विभिन्न स्तरों पर स्थानिक योजनाएं तैयार की जा सकती हैं वे हैं:

परिप्रेक्ष्य योजना: दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य विजन दस्तावेज (20-30 वर्ष की समय सीमा)
क्षेत्रीय योजना: क्षेत्र और क्षेत्रीय संसाधनों को परिभाषित करता है (20 वर्ष)
विकास योजना: जिला विकास योजना, मास्टर प्लान (10-20 वर्ष; हर 5 साल में समीक्षा)
स्थानीय क्षेत्र योजना: नगर नियोजन योजनाएं, उप-नगर योजनाएं (5-20 वर्ष)

स्थानिक योजना भूमि प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है, जो मास्टर प्लान के रूप में शहर/क्षेत्र के सतत विकास के लिए विस्तृत भूमि उपयोग आवंटन प्रदान करता है और शहरी क्षेत्रों में योजना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इनमें से अधिकांश स्थानिक योजनाएं आवधिक समीक्षा और संशोधन के लिए पांच वर्षों के चरणों में 10-20 वर्षों की अवधि के लिए बनाई जाती हैं।

★ कंसल्टेंट, स्वामित्व, पंचायती राज मंत्रालय

स्थानिक योजनाओं की तैयारी एक संपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें हितधारक परामर्श के रूप में सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बहुत सारे डेटा संग्रह और स्थिति विश्लेषण शामिल हैं। स्थानिक योजना की तैयारी में शामिल हैं:

क्षेत्र की स्थानिक योजना प्रकृति में बहु-विषयक है, जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता और विभिन्न पहलुओं के बीच सभी अंतर्संबंधों को ध्यान में रखती है; इसमें सामाजिक पहलुओं, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, वास्तुकला आदि जैसे अध्ययन के विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। यह 'सामुदायिक भागीदारी' पर आधारित है और विकास के लिए एक 'विजन' का नेतृत्व करता है। परिवर्तन और भूमि विकास अंतिम स्थानिक योजना दस्तावेज के अनुसार होता है।

जबकि शहरी क्षेत्र के लिए स्थानिक योजना एक वैधानिक उपकरण है, जो अधिकांश राज्यों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियमों द्वारा समर्थित है, ग्रामीण क्षेत्र में, न तो मौजूदा योजना ढांचे में स्थानिक योजना दृष्टिकोण है और न ही ग्राम पंचायत के लिए विशेष रूप से स्थानिक योजनाओं के लिए वैधानिक प्रावधान है।

पंचायतों की भूमिका

पंचायतें, ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं (पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित) लोगों और सरकारी मशीनरी के बीच इंटरफेस प्रदान करती हैं। इस प्रकार उन पर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और देश के लिए आर्थिक विकास के चालक के रूप में कार्य करने के लिए स्थानिक योजना को एक उपकरण के रूप में अपनाने की जिम्मेदारी है। इसलिए, यह स्वाभाविक परिणाम है कि पंचायतें अपने घटक गांवों के सभी क्षेत्रों में स्थानीय आर्थिक विकास के बड़े कैनवास को संभालने में सक्षम होंगी, जो कि भारत में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की गई स्थानिक विकासात्मक योजना के समान है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय योजना बनाने के लिए एमओपीआर की पहल

एमओपीआर की वर्तमान पहल में स्थानिक योजना और उसे ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। MoPR ने ग्रामीण विकास मानकों को व्यवस्थित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (RADPFI) दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

दिशानिर्देश गांव की भूमि उपयोग योजना पर कनेक्टिविटी, पर्यावरणीय पहलुओं और बुनियादी ढांचे के अधिरोपित मानकों पर जोर देते हैं। दिशानिर्देशों के उद्देश्य हैं:

1. ग्रामीण/ग्राम पंचायत विकास के लिए स्थानिक मानकों पर पहुंचने के लिए,

2. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करने में सहायता के लिए मानदंड और मानक शामिल हैं,

3. दिशानिर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए संस्थागत ढांचे की सिफारिश करना और ग्राम पंचायतों के नियोजित विकास के लिए एक रोडमैप प्रदान करना।

पिछले दशक में, वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली (जीएनएसएस), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), उपग्रह रिमोट सेंसिंग (आरएस) आदि जैसी भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों ने सूक्ष्म और स्थूल स्तर पर ग्रामीण नियोजन में महत्व प्राप्त किया है। MoPR द्वारा कार्यान्वित स्वामित्व योजना एक ऐसी पहल है और राष्ट्रीय महत्व की योजना है क्योंकि यह आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान कर रही है, जो पहले उपलब्ध नहीं थे।

स्वामित्व योजना के तहत, आबादी क्षेत्रों के विस्तार की पहचान की जाती है, गांवों के आबादी क्षेत्रों का ड्रोन सर्वेक्षण किया जाता है, जीआईएस प्लेटफॉर्म पर संपत्तियों की सुविधा निकाली जाती है और संपत्ति कार्ड बनाए जाते हैं और संपत्ति मालिकों को वितरित किए जाते हैं। गाँव. संपत्ति के मालिक अपनी संपत्तियों का वित्तीय रूप से मुद्रीकरण कर सकते हैं और अपने व्यवसाय की स्थापना या विस्तार के साथ-साथ अपनी संपत्तियों के बेहतर निर्माण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए बैंक ऋण का लाभ उठा सकते हैं। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद दर में कमी आ रही है, बल्कि एक डेटा बेस भी तैयार किया जा रहा है, जो आबादी क्षेत्रों में स्थानिक योजना के साथ-साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। पंचायतों में विकास नियंत्रण विनियम लागू करने की सहायता से असंगठित विकास को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। इसके अलावा, बिल्डिंग परमिशन सिस्टम की शुरुआत से न केवल नई इमारतों की सुरक्षा और बेहतर डिजाइन सुनिश्चित की जा सकती है, बल्कि इससे राजस्व का अपना स्रोत (ओएसआर) बनाने में भी मदद मिलेगी।

पंचायती राज मंत्रालय ने भारत के 14 राज्यों में 17 भागीदार योजना और वास्तुकला संस्थानों जैसे एसपीए, सीईपीटी, एनआईटी, आईआईटी और राष्ट्रीय ख्याति के अन्य संस्थानों की मदद से 34 ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजनाएं (जीपीएसडीपी) तैयार की थीं। तैयार किए गए जीपीएसडीपी चयनित 34 पंचायतों की मौजूदा स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने, बुनियादी ढांचे (भौतिक और साथ ही सामाजिक) की सेवा वितरण से संबंधित मुद्दों की पहचान करने, आगामी 10-20 वर्षों के लिए विभिन्न जरूरतों को पेश करने और आधारित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुए हैं। अनुमानों के अनुसार बेहतर विकास के लिए परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की आवश्यकता है। तैयार योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के स्थानिक विश्लेषण, आधार-मानचित्र की तैयारी, सर्वेक्षण आदि पर आधारित थीं।

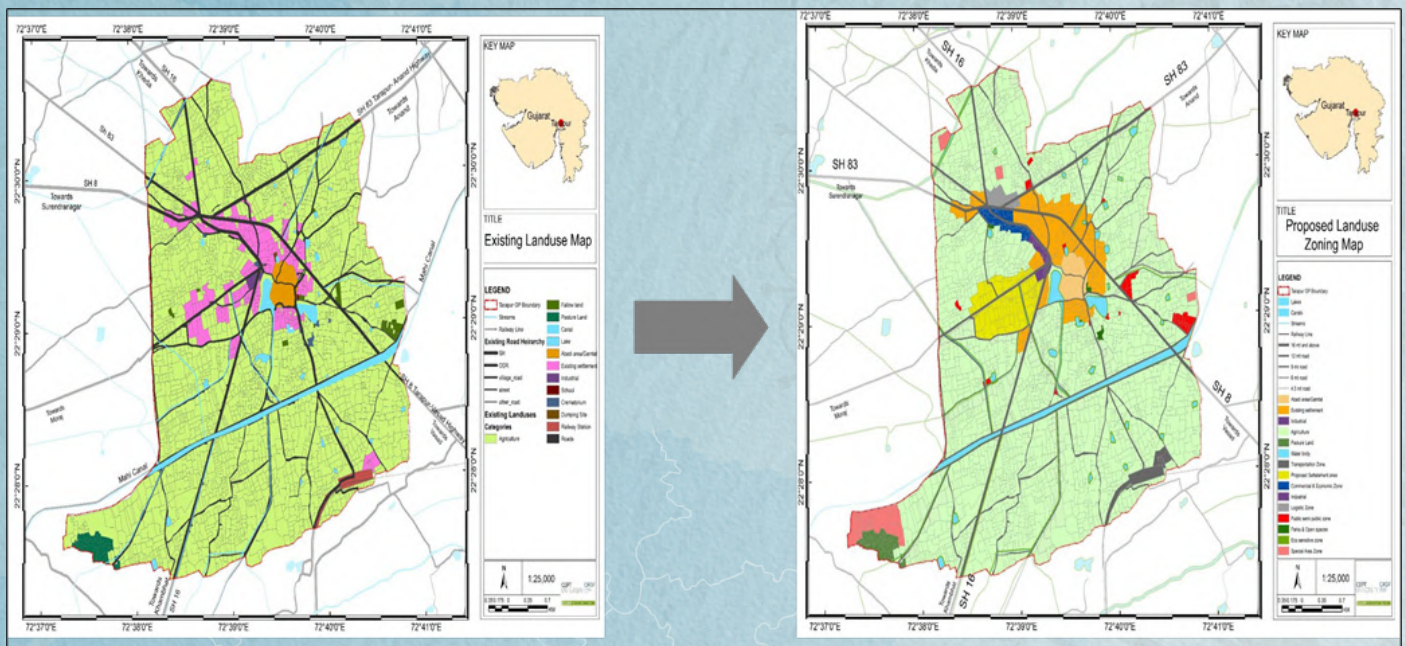

Existing Landuse **Proposed Landuse**

इन पहलों के अनुसरण में, यह उम्मीद की जाती है कि अधिक ग्राम पंचायतें कृषि, निवास, स्थानीय बाजारों, पार्कों, जल निकायों, कृषि-आधारित उद्योगों के लिए स्पष्ट रूप से क्षेत्रों का सीमांकन करते हुए अपने गांवों की स्थानिक योजना तैयार कर सकेंगी। MSMEs संस्थागत क्षेत्र जैसे बैंक, डाकघर, आंगनवाड़ी, पीएचसी, स्कूल, परिवहन बुनियादी ढांचा, हरित सार्वजनिक स्थान बनाना और भागीदारी और समावेशी तरीकों से ग्रामीण योजना और प्रबंधन में सुधार करना है।

एक मजबूत योजना एक प्रभावी विकास रणनीति के लिए दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करेगी। ऐसी योजना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम अन्य बातों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के लिए राजस्व के अपने स्रोतों (ओएसआर) के तत्काल और भविष्य के स्रोतों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप का सीमांकन भी होगा जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा।

तैयार की गई स्थानिक योजनाओं का लक्ष्य व्यवस्थित नियोजित बुनियादी ढांचे का विकास प्रदान करना, पंचायतों की स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता देना, संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, सुविधाओं का प्रभावी वितरण और स्थानीय पहचान को मजबूत करने के साथ विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना और भविष्य के नीतिगत निर्णयों के लिए एक रूपरेखा तैयार करना होगा। यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के सतत लक्ष्य 11 को पूरा करेगा जो "स्थायी शहरों और समुदायों" के बारे में है। यह स्थानिक नियोजन अभ्यास भूमि मालिकों, डेवलपर्स और सरकारी अधिकारियों को खुली और लोकतांत्रिक योजना को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ग्रामीण क्षेत्र वास्तव में विकास के अंकुर हैं, जिन्हें बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण दिया जाए तो वे विकसित होंगे, लेकिन उन्हें पोषित करने के लिए हमें उन्हें विकास के लिए सही दिशा/पैटर्न देने की आवश्यकता है। दिशा में सभी टिकाऊ प्रथाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास के सभी अवसरों का उपयोग करते हुए उपलब्ध दुर्लभ संसाधनों, विशेष रूप से भूमि को संरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए, जो निश्चित रूप से इसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। इसलिए, पारंपरिक विकास विधियों के साथ-साथ, स्थानिक योजना निश्चित रूप से भविष्य के विकास के लिए रोडमैप के रूप में काम करेगी, जो कई संभावनाओं का उपयोग करेगी, विभिन्न नए अवसरों को खोलेगी और ग्रामीण भारत की कई समस्याओं का समाधान करेगी। एमओपीआर द्वारा किए गए प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाकर और उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए उनकी निरंतर और कठोर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इसके अलावा, इस दिशा में एक मजबूत सुधार निश्चित रूप से गांधी जी के "ग्राम स्वराज" के दृष्टिकोण को संभव बनाएगा।

****

स्वामित्व योजना के तहत बनाए गए संपत्ति कार्डों में सह-स्वामित्व के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

★ आभास व्यास

विश्व स्तर पर, महिलाओं के पास कम जमीन है और पुरुषों की तुलना में जमीन पर उनका सुरक्षित अधिकार भी कम है। विश्व के भूमिधारकों में औसतन 20 प्रतिशत से भी कम महिलाएं हैं, लेकिन कृषि श्रम शक्ति में उनकी हिस्सेदारी अनुमानित 43 प्रतिशत है।

भूमि सुधार, आवंटन, और स्वामित्व या पंजीकरण कार्यक्रम अक्सर परिवार को लक्षित करते हैं, या "घर के मुखिया" को स्वामित्व सौंपते हैं, जिसे अक्सर पुरुष के रूप में परिभाषित किया जाता है। चूँकि महिलाओं को आमतौर पर भूमि-मालिक या किसान नहीं माना जाता है, इसलिए उन्हें आमतौर पर विस्तार और सहायता कार्यक्रमों और वित्तीय ऋण और ऋण से बाहर रखा जाता है जो भूमि के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक हैं।

सुरक्षित भूमि अधिकारों के अभाव में, महिलाएं विभिन्न सामाजिक पीड़ाओं के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं और अक्सर उनके पास कोई सहारा नहीं होता है। इसके विपरीत, जब महिलाओं के पास भूमि पर सुरक्षित अधिकार होते हैं, तो असंख्य लाभ मिलते हैं। भूमि और उत्पादक संपत्तियों पर महिलाओं के मजबूत अधिकार बढ़ी हुई स्थिति, बेहतर जीवन स्थितियों, बेहतर पोषण और खाद्य संप्रभुता, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा परिणामों, उच्च कमाई और व्यक्तिगत बचत, और ऋण तक बेहतर पहुंच के साथ-साथ लिंग हिंसा से बेहतर सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्य 1- उपलक्ष्य-1.4.2 उन नीतियों के परिणामों को मापता है जिनका उद्देश्य महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों सहित सभी के लिए कार्यकाल सुरक्षा को मजबूत करना और महिलाओं की भूमि पर सरकार को वैश्विक मार्गदर्शन प्रदान करना है। कानून और व्यवहार में अधिकार। महिलाओं को व्यवहार में अपने भूमि अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए, राज्यों को उन कानूनों और सामाजिक मानदंडों को तत्काल बदलना चाहिए जो महिलाओं के भूमि के स्वामित्व और उस तक पहुंच के अधिकार में बाधाएं डालते हैं।

मध्य प्रदेश ने संपत्ति कार्ड (अधिकार अभिलेख) में महिला सह-मालिकों का नाम शामिल करना अनिवार्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में प्रावधान किया है।

****

पुणे जिला परिषद ने संपत्ति पर महिलाओं के स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के लिए 8 महीने तक एक विशेष अभियान चलाया।

पुणे जिले में 88% आवासीय संपत्तियाँ (9.27 लाख में से 8.15 लाख) अब संयुक्त रूप से या पूरी तरह से घर की महिला सदस्यों के स्वामित्व में हैं। जब अभियान शुरू हुआ तो यह 16% था।

महिलाओं द्वारा संपत्ति का स्वामित्व उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करता है और उद्यम स्थापित करने और अन्य उद्देश्यों आदि के लिए बैंकों से उधार लेने में सहायता करता है।

स्वामित्व योजना ने राज्यों को अपने भूमि अधिनियमों में संशोधन करने और संपत्ति कार्ड में महिलाओं के सह-स्वामित्व को शामिल करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व विवरण एकत्र करते समय महिलाओं को सह-मालिक के रूप में शामिल करने के लिए राज्यों को सलाह भी जारी की है और राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार, 13 राज्यों ने संपत्ति कार्ड में महिलाओं के सह-स्वामित्व का प्रावधान किया है।

"स्वामित्व योजना के माध्यम से प्राप्त अधिकार अभिलेख ने हमें गांव में अपनी जमीन सुरक्षित करने में मदद की है" - श्रीमती शालिया सिद्दीकी, हरदा, मध्य प्रदेश

"स्वामित्व योजना के माध्यम से प्राप्त संपत्ति कार्ड हमें बैंकों से ऋण सुरक्षित करने में मदद करेंगे। संपत्ति संबंधी विवाद भी कम हुए हैं"-श्रीमती गरिमा सोनी, निवासी, हरदा, मध्य प्रदेश

★ कंसल्टेंट, स्वामित्व, पंचायती राज मंत्रालय

ग्राम स्वराज हासिल करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम

★ शिवम रंजन

स्वामित्व योजना के तहत वितरित संपत्ति कार्डों ने योजना के वास्तविक लाभों का एहसास करने में मदद करके भारत में ग्रामीण आबादी के जीवन को बदल दिया है। दशकों के बाद ग्रामीण आबादी के लिए एक वैध भूमि स्वामित्व दस्तावेज की लंबे समय से चली आ रही चिंता को दूर करते हुए, इस योजना में संपत्ति कार्ड बनाने पर विचार किया गया है जिसका उपयोग बैंकों से ऋण प्राप्त करने और लाभार्थियों द्वारा अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में किया जा सकता है। ग्रामीण लोग स्थिरता के लिए अपनी संपत्तियों का मूल्य बढ़ाने के लिए अपनी संपत्तियों पर घर बना सकते हैं। SVAMITVA योजना के माध्यम से प्रदान किए गए अधिकारों के तहत नागरिक अपनी संपत्ति को पट्टे पर दे सकते हैं या बेच सकते हैं।

"स्वतंत्र भारत को "स्थानीय के लिए मुखर" होना चाहिए और नागरिकों को 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उत्पादों का महिमामंडन करना चाहिए। जबकि हम आर्थिक वृद्धि और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मानवता को इस प्रक्रिया और हमारी यात्रा में एक केंद्रीय भूमिका बनाए रखनी चाहिए," -श्री नरेंद्र मोदी

यह योजना इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है कि पीढ़ी को स्वतंत्र रूप से कार्य गतिविधियों को करने और बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर बनने के लिए सीखने के भरपूर अवसर प्रदान किए जाएं। आत्मनिर्भर होने के मिशन को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए योजना गतिविधियों के सभी पहलुओं में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा योजना के तहत कई उदाहरण अपनाए गए हैं।

योजना प्रक्रिया पर राज्य के अधिकारियों का कौशल प्रशिक्षण:

योजना की रूपरेखा में ड्रोन छवियों के निर्माण से लेकर अंतिम मानचित्रों की छपाई तक राज्य विभागों द्वारा मानचित्रों के सत्यापन का व्यापक अभ्यास शामिल है। संपत्ति कार्ड की तैयारी से पहले अंतिम मानचित्रों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों द्वारा समन्वय में कई पुनरावृत्तियां की जाती हैं। संपत्तियों के सीमांकन की पटवारियों द्वारा गहनता से जांच की जानी आवश्यक है। ड्रोन उड़ान के पूरा होने के बाद उत्पन्न फीचर निकाले गए मानचित्रों की जांच के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य द्वारा जिला स्तर पर पटवारियों को व्यापक और उचित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। यह राज्य के अधिकारियों और पटवारियों को अन्य संलग्न परियोजनाओं और क्षेत्रों में मानचित्र कौशल का उपयोग करने की अनुमति देता है

ड्रोन सर्वेक्षण के लिए पायलटों का प्रशिक्षण:

भारतीय सर्वेक्षण विभाग नियमित रूप से योजना के तहत इन-हाउस मैनपावर और कर्मियों को पायलट प्रशिक्षण दे रहा है। इससे मिशन के दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय सर्वेक्षण कार्यबल के ड्रोन संचालन कौशल का विकास हुआ है

सीओआरएस के पास विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्योग अनुप्रयोग हैं जिनका उपयोग संबंधित विभागों द्वारा किया जा सकता है। इसका सटीक भू-संदर्भ, जमीनी सच्चाई और भूमि का सीमांकन प्रदान करने का लाभ है।

★ कंसल्टेंट, स्वामित्व, पंचायती राज मंत्रालय

भारतीय सर्वेक्षण राज्य विभागों को सीओआरएस प्रौद्योगिकी के उपयोग के मामलों पर जानकारी प्रदान करने के लिए सत्र भी आयोजित कर रहा है। इससे ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण, सिंचाई और बुनियादी ढांचे आदि जैसे विकास कार्यों में आसानी होगी।

योजना के तहत रोजगार के अवसर सृजित

भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा डिजिटाइज़र की नियुक्ति

डेटा प्रोसेसिंग, फीचर निष्कर्षण, विशेष जानकारी को अपडेट करने और अंतिम मानचित्रों में सुधारों को शामिल करने के माध्यम से ड्रोन छवियों के निर्माण में डिजिटाइज़र की महत्वपूर्ण भूमिका है। SVAMITVA योजना ने समय सीमा के भीतर योजना के तहत गांवों की व्यापक संख्या को कवर करने के लिए डिजिटाइज़र के लिए रोजगार के अवसरों का एक पुल बनाया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने राज्य स्तर पर अपने कार्यालय स्थापित किए हैं जहां राज्य विभागों के परामर्श से कार्यान्वयन गतिविधियों को तेजी से ट्रैक करने के लिए पर्याप्त संख्या में डिजिटाइज़र को काम पर रखा जाता है।

राज्यों द्वारा जनशक्ति की नियुक्ति

योजना के तहत, कुछ राज्यों ने नक्शों के जमीनी सत्यापन, नक्शों को अंतिम रूप देने के लिए पूछताछ जैसी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राज्य स्तर पर युवा पेशेवरों और सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित अपनी जनशक्ति में वृद्धि की है, जिससे योजना के तहत रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा हो रहे हैं।

योजना कार्य को निजी एजेंसियों को आउटसोर्स करना

यह योजना निर्धारित समय-सीमा के भीतर कवर की जाने वाली व्यापक गतिविधियों और लक्ष्यों को शामिल करती है। लक्ष्य और निर्धारित समय सीमा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को योजना के काम को अन्य डोमेन एजेंसियों को आउटसोर्स करने की अत्यधिक आवश्यकता थी। ड्रोन उड़ान, ड्रोन मानचित्रों का निर्माण जैसी विभिन्न योजना गतिविधियों को निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया गया था, जो बाजार में अपनी स्थापना के लिए निजी और स्टार्टअप फर्मों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और व्यावसायिक अवसर उत्पन्न कर रही थीं।

मनरेगा मजदूरों की नियुक्ति

कुछ राज्यों ने गांवों में ड्रोन उड़ान शुरू करने से पहले गांवों में चूना मार्किंग करने के लिए मनरेगा श्रमिकों को काम पर रखा है। इस गतिविधि में बड़ी संख्या में आबादी वाले गांवों को चिह्नित करने के लिए बड़े पैमाने पर जनशक्ति की तैनाती शामिल है।

परियोजना निगरानी इकाइयों की स्थापना

इस योजना में स्वामित्व कार्यान्वयन और इसके प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की बेहतर निगरानी के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर परियोजना निगरानी इकाइयों की स्थापना शामिल थी। पीएमयू कार्यान्वयन और हितधारक समन्वय की समग्र प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार है, जिसमें जागरूकता की सुविधा और सहायता प्रदान करना शामिल है। केंद्र और राज्य स्तर पर पीएमयू की तैनाती से परामर्श फर्मों को व्यावसायिक अवसर मिलने के साथ-साथ सभी राज्यों में रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है।

योजना के अंतर्गत तकनीकी परिवर्तन

इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि जैसी अत्याधुनिक तकनीक को एकीकृत करके एक स्वचालित, सहयोगात्मक और भागीदारीपूर्ण भूमि प्रशासन प्रणाली संभव बनाई जाएगी। भू-स्थानिक डेटा और प्रौद्योगिकी के साथ भूमि प्रशासन के गतिशील और लगातार बढ़ते परिदृश्य से जुड़ी बदलती चुनौतियों का समाधान करना है। डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करने के लिए योजना के तहत कई तकनीकी उन्नयन शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाना, संपत्ति विवादों को कम करना, ग्राम पंचायतों (जीपी) में संपत्ति कर का सटीक निर्धारण, जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पंचायत-स्तरीय योजना में सहायता के लिए मानचित्र विकसित करना और बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाएं और मानचित्र तैयार करना है।

सर्वेक्षण अवसंरचना में उन्नयन:

डीजीपीएस सर्वेक्षण (प्रिज्म का उपयोग करके) से आधुनिक सीओआरएस सर्वेक्षण (रोवर्स का उपयोग करके) को अपनाने के लिए सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ है। योजना में स्थिति में बेहतर सटीकता प्राप्त करने और क्षेत्र सर्वेक्षण करने में कम समय लेने के लिए सीओआरएस की अद्यतन सर्वेक्षण तकनीक को शामिल किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया पूरे देश में योजना के तहत राष्ट्रीय सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना कर रहा है। 5 cm से बेहतर स्थितिगत सटीकता के साथ, राष्ट्रव्यापी सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना से विस्तृत परियोजना की तैयारी के साथ-साथ कृषि, बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, उपयोगिताओं, सिंचाई, रेलवे दूरसंचार जैसे हर क्षेत्र के लिए व्यापक प्रभाव और उपयोग के मामले होंगे।

सैटेलाइट इमेज प्रोक्योरमेंट से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक में संक्रमण:

इस योजना में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण करना शामिल है। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की बेहतर रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरें खींचने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों के बजाय ड्रोन सर्वेक्षणों की ओर बदलाव ग्रामीण भारत में प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों में से एक रहा है।

उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले गांवों के नक्शे आधार मानचित्र परतों की तैयारी के लिए इमारतों, सड़कों, भूमि पार्सल, पानी के टैंक, खुले भूखंडों आदि जैसी सभी दृश्यमान विशेषताओं के फीचर निष्कर्षण के लिए काम कर सकते हैं।

तस्वीरों के रिज़ॉल्यूशन में वृद्धि: पूरे भारत में बड़े पैमाने पर मैपिंग की जाती है और स्वामित्व संपत्ति अधिकार प्रदान करने के लिए ग्रामीण आबादी क्षेत्र के लिए सटीक मानचित्र तैयार करने के लिए SVAMITVA के तहत 5 सेमी स्थानिक रिज़ॉल्यूशन के उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा मानचित्र बनाए जाते हैं।

सर्वेक्षण गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले सर्वेक्षण ग्रेड ड्रोन सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों के लिए 5 सेमी सटीकता की उच्च रिज़ॉल्यूशन छवियों के साथ 1:500 के पैमाने पर मानचित्र बनाने में सक्षम बनाते हैं।

3D ग्राम मानचित्रों का निर्माण: योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण कच्चे डेटा के एक भाग के रूप में जमीनी विशेषताओं के ऊंचाई घटक को कैप्चर करता है और सर्वेक्षण किए गए आबादी गांवों के लिए 20 सेमी ऊर्ध्वाधर सटीकता के डीईएम (डिजिटल एलिवेशन मॉडल) उत्पन्न करता है जिसका उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। भू-भाग की विशेषताएं जैसे किसी भी बिंदु पर ऊंचाई, ढलान और ढांचागत प्रबंधन, जल विज्ञान और प्रवाह-दिशा अध्ययन, भूमि-उपयोग योजना और स्थलाकृतिक मानचित्रों की रूपरेखा तैयार करना।

DEM प्रोफ़ाइल सभी गांवों की विशेषताओं की सापेक्ष ऊंचाइयों का सीमांकन कर सकती है और पूरे भारत में पंचायतों के लिए ग्राम स्तर पर उच्च जानकारीपूर्ण 3डी मानचित्र बनाने में मदद करेगी।

मानचित्र अभिलेखों का अपडेट

यह योजना राज्यों को पुराने अव्यवस्थित मानचित्रों को समृद्ध स्वामित्व डेटा से उत्पन्न डिजिटल मानचित्रों में अपडेट करने का अवसर प्रदान करती है। इससे मानचित्र रिकॉर्ड को अधिक प्रस्तुत करने योग्य, स्पष्ट और जानकारीपूर्ण अद्यतन करने में मदद मिलेगी।

भूमि प्रबंधन को व्यवस्थित करने में SVAMITVA योजना के माध्यम से किए गए प्रयास और योगदान ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को ऊपर उठाने और ग्राम पंचायतों के कार्य को बढ़ाने के लिए दृढ़ समर्पण को दर्शाते हैं, जिससे उन्हें देश भर में रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ अपने कौशल को विकसित करने के कई अवसर मिलते हैं। नागरिकों को "आत्मनिर्भर" और "आत्मनिर्भर" बनाने के स्तर। इस योजना ने ग्रामीण भारत की बेहतर योजना और विकास के ढांचे में तकनीकी प्रगति को शामिल किया है।

****

आत्मनिर्भर पंचायतें
स्वामित्व डेटा का उपयोग करके संपत्ति कर के सटीक मूल्यांकन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के राजस्व के अपने स्रोतों को बढ़ाना

★ वात्सल्य मालवीय

भारत में पंचायतें जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, उनके पास अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण के कई स्रोत हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तपोषण के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक संपत्ति कर है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (एच) के तहत संपत्ति कर लगाने की शक्ति राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों के पास निहित है। संपत्ति कर स्थानीय सरकारी निकायों, जैसे ग्राम पंचायत या नगर पालिका द्वारा व्यक्तियों या संस्थाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर लगाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, संपत्ति कर आमतौर पर कृषि भूमि, आवासीय संपत्तियों और वाणिज्यिक संपत्तियों पर लगाया जाता है। संपत्ति कर की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है और स्थानीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

संपत्ति कर को व्यवस्थित करने की आवश्यकता

ग्रामीण भारत में संपत्ति कर विभिन्न राज्यों और नगर पालिकाओं में व्यापक रूप से भिन्न होता है। संपत्ति कर संग्रह ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर सकता है, जिसका उपयोग विभिन्न पहलों और बुनियादी ढांचे के विकास कार्यक्रमों को निधि देने के लिए किया जा सकता है। इससे अन्य लाभों के अलावा बेहतर जीवन स्तर, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और परिवहन सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं।

कर संग्रह स्थानीय शासन को प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि यह स्थानीय निकायों को अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संपत्ति कर से उत्पन्न राजस्व का उपयोग उन पहलों को वित्त पोषित करने के लिए किया जा सकता है जो स्थानीय आबादी को लाभान्वित करती हैं, जिससे बेहतर रहने की स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास होता है। संग्रह स्थानीय समुदायों को सशक्त बना सकता है, क्योंकि यह उन्हें अपने क्षेत्रों के विकास में योगदान करने में सक्षम बनाता है। इसका उपयोग स्थानीय शासन में सामुदायिक भागीदारी और जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है, जिससे निर्णय लेने में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी।

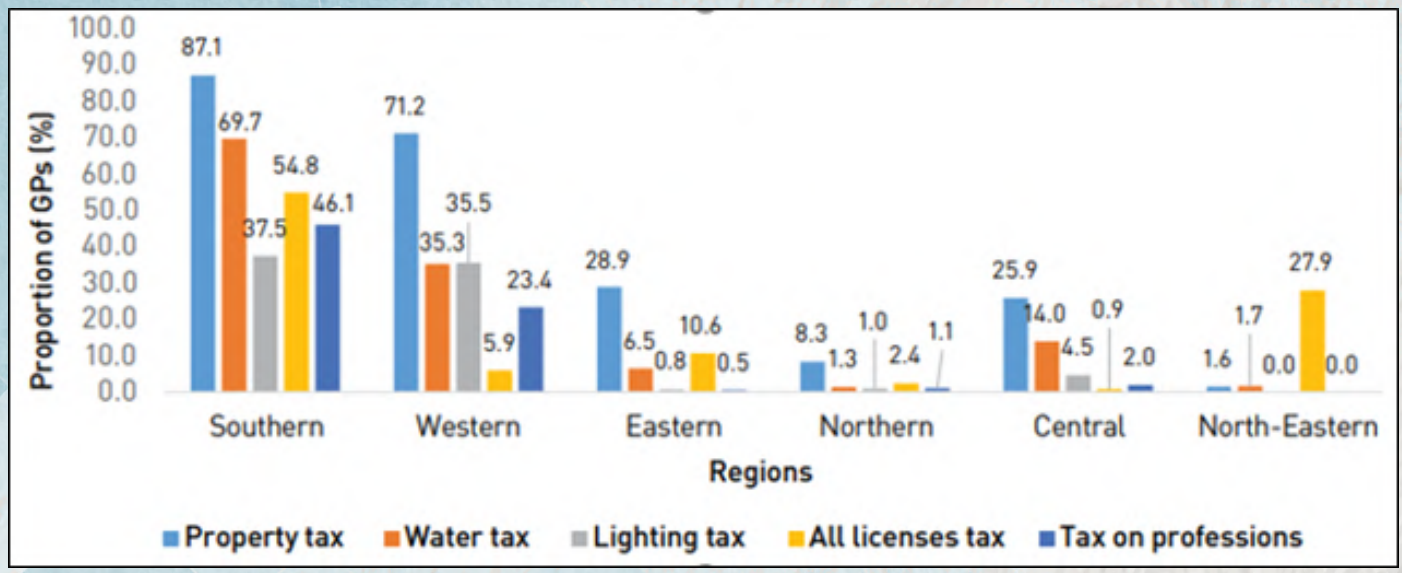

उपरोक्त तस्वीर से पता चलता है कि भारत में संपत्ति कर और जीडीपी का अनुपात G20 देशों में सबसे कम में से एक है। भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, संपत्ति कर के निर्धारण की आवश्यकता है जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है।

★ कंसल्टेंट, स्वामित्व, पंचायती राज मंत्रालय

इसके अलावा पंद्रहवें वित्त आयोग ने जुलाई-दिसंबर 2018 (DWSHH 2018) में पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छता और आवास स्थितियों पर आयोजित एनएसएसओ के 76वें दौर के यूनिट स्तर के डेटा का उपयोग करके सभी राज्यों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हाउस टैक्स क्षमता का अनुमान लगाया है।). यह अनुमान लगाया गया है कि चुनिंदा पांच राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में उनकी क्षमता के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में गृह कर का संग्रह औसतन लगभग 20% है। 2019 की कीमतों पर प्राप्त गृह कर संग्रह की कुल क्षमता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 42,160 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, पंचायतों के पास संपत्ति कर के संग्रह में सुधार करके अपने स्वयं के स्रोत राजस्व को बढ़ाने की एक बड़ी क्षमता है।

ग्रामीण भारत में संपत्ति कर एकत्र करने की चुनौतियां:

कई ग्रामीण क्षेत्रों में, संपत्ति के रिकॉर्ड अधूरे, पुराने या अस्तित्वहीन हैं। इससे उन संपत्तियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है जिन पर कर लगाने की आवश्यकता है। जागरूकता की कमी, सीमित प्रवर्तन और इस धारणा के कारण कि कर नागरिकों के लिए फायदेमंद नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कर अनुपालन अक्सर कम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे का अभाव है, जिससे स्थानीय अधिकारियों के लिए कर एकत्र करना और कर नियमों को लागू करना मुश्किल हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सीमित वित्तीय संसाधन होते हैं, जो प्रौद्योगिकी और कर्मचारियों के प्रशिक्षण जैसे कर संग्रह बुनियादी ढांचे में निवेश करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर कर संग्रह का प्रबंधन करने के लिए सीमित कर्मचारी होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कर संग्रह प्रक्रिया में अक्षमताएं और देरी हो सकती है। कुछ मामलों में, संपत्ति कर संग्रह का प्रबंधन सरकार के विभिन्न स्तरों पर कई अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिससे कर संग्रह प्रक्रिया में भ्रम और देरी हो सकती है।

हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत का संपत्ति कर संग्रह ओईसीडी देशों की तुलना में बहुत कम है। शहरी संपत्ति कर जीडीपी के 0.2% के अधीन है और ग्रामीण संपत्ति कर इसका लगभग आधा है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें संपत्ति रिकॉर्ड में सुधार, जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से कर अनुपालन बढ़ाना, बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में निवेश करना और अक्षमताओं को कम करने के लिए कर संग्रह प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना शामिल है। स्थानीय सरकारी अधिकारियों को भी स्थानीय विकास पहलों के लिए बढ़े हुए राजस्व के लाभों पर जोर देते हुए, संपत्ति कर संग्रह के लिए समर्थन बनाने के लिए समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

स्वामित्व योजना और इसके लाभ:

SVAMITVA योजना का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह संपत्ति मालिकों को संपत्ति के अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिसका उपयोग क्रेडिट और अन्य सरकारी योजनाओं तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। ग्राम पंचायतें इन अभिलेखों का उपयोग संपत्ति कर का सटीक आकलन करने के लिए भी कर सकती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक है।

राज्य जो संपत्ति कर के संदर्भ में स्वामित्व योजना से लाभान्वित हो सकते हैं:

• **कर्नाटक:** कर्नाटक उन राज्यों में से एक है जिसने SVAMITVA योजना लागू की है। योजना के तहत तैयार किए गए डिजिटल मानचित्र सरकार को भूमि पार्सल की सटीक सीमाओं की पहचान करने और संपत्ति कर की सही मात्रा की गणना करने में सक्षम बना सकते हैं। राज्य ने ग्रामीण गैर-कृषि संपत्तियों के लिए वृद्धिशील दृष्टिकोण में स्वामित्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक पहल ***E-SWATHU*** भी शुरू की है, जिसका उपयोग संपत्तियों के लेनदेन और कर संग्रह में ग्राम पंचायतों की सहायता के लिए किया जा सकता है।
• **आंध्र प्रदेश –** राज्य डिजिटल पंचायत पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर एकत्र करता है। यह पोर्टल राज्य की ग्राम पंचायतों के सभी परिवारों का डेटाबेस होस्ट करता है। एप्लिकेशन के माध्यम से, पंचायत/नागरिक मांग उठा सकते हैं, और बाद में कर का संग्रह किया जा सकता है।
• **मध्य प्रदेश:** मध्य प्रदेश ने स्वामित्व योजना लागू की है और भूमि मालिकों से संपत्ति कर एकत्र करने के लिए योजना के तहत तैयार किए गए डिजिटल मानचित्रों का उपयोग आगे बढ़ाया जा सकता है। मानचित्रों ने सरकार को संपत्तियों की पहचान करने और कर राशि की सटीक गणना करने में सक्षम बनाता है।

राज्य ने संपत्ति कर के संग्रह के लिए अपना स्वयं का ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया है, जिसे स्वकराधान प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है, जो समग्र डेटाबेस के साथ भी एकीकृत है। 7.79 लाख परिवारों ने संपत्ति कर पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। 30.30 करोड़ रुपये टैक्स लगाया गया है, जिसमें से 9.03 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं।

स्वामित्व की दहलीज पर हिमाचल प्रदेश

★ डॉ राजीव बंसल

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। पंचायत राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीक के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाली भूमि का सीमांकन किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में योजना की स्थिति:

हिमाचल प्रदेश में, योजना के तहत कवरेज के लिए कुल 15196 गांवों की पहचान की गई है। स्वामित्व योजना के कार्यान्वियन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। ड्रोन उड़ाने की प्रक्रिया सबसे पहले सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) की मदद से जिला हमीरपुर में शुरू की गई थी और जिला कुल्लू को छोड़कर सभी जिलों में ड्रोन उड़ाने का काम जारी है। भारत सरकार सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) फंड के माध्यम से धनराशि प्रदान कर रही है जो राज्य को रुपये की दर से प्रदान की जा रही है। आईईसी गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रति गांव 500 रु. आईईसी के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) से भी धनराशि का अतिरिक्त प्रावधान किया जा सकता है। आबादी डीह गांव के चूना चिन्हांकन के दौरान श्रम एवं सामग्री की लागत के लिए एमजी नरेगा, 15वें वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) से धनराशि का प्रावधान किया गया है। स्वामित्व योजना को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च, 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नवीनतम जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में कुल 15196 आबादी देह गाँव में से, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार व्यापक मानचित्र पूरा कर लिया गया है:

(Villages in No.)

Sr. No	District	Total abadi deh villages	ISM Competed in villages
1.	Bilaspur	829	358
2.	Chamba	1069	88
3.	Hamirpur	1505	1505
4.	Kangra	3156	274
5.	Kinnaur	157	36
6.	Kullu	378	4
7.	Lahaul –Spiti	217	95
8.	Mandi	2574	286
9.	Shimla	2036	173
10.	Sirmaur	724	260
11.	Solan	2025	613
12.	Una	526	405
	Total	**15196**	**4097**

★ संयुक्त निदेशक एवं फैकल्टी सदस्य, हि.प्र. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान - शिमला

जिला चम्बा, कांगड़ा और कुल्लू में एक-एक ड्रोन टीम काम कर रही है और जिला बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में दो-दो टीमें काम कर रही हैं; राज्य में कुल 13 ड्रोन टीमें काम कर रही हैं। जिला हमीरपुर में 119 गांव (जिनमें 1285 लाभार्थी हैं) संपत्ति कार्ड वितरण के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, जिला हमीरपुर में 354 गांवों के मानचित्र आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए प्रदर्शित किये गये हैं। जिला मंडी में कैंप कार्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, कांगड़ा और शिमला में कैंप कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है और यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक कार्यात्मक हो जाएगा। पहल को और सुविधाजनक बनाने के लिए, आरएमएस पोर्टल पर स्वामित्व डैशबोर्ड को स्वामित्व योजना के विभिन्न घटकों की प्रगति की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य एनआईसी ने अधिकारों के रिकॉर्ड (संपत्ति काड) के निर्माण और अद्यतनीकरण के लिए मॉड्यूल को डिजाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसमें लगभग एक महीने का समय लगेगा संपत्ति कार्ड का निर्माण 1 अप्रैल, 2023 से शुरू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री, एचपी ने वर्ष 2023-24 के अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि इस वित्तीय वर्ष में काम पूरा कर लिया जाएगा और राज्य में संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। विस्तृत स्थिति नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत की गई है:

Sr. No	District	Abadi DehVillages	Outer Boundary Demarcation (Completed)	Large Scale Mapping	1st Stage Maps Collected from SoI Villages	Villages Ground Truthing (Completed)	Village (Maps displayed in GP/Patwar Khana)	Final Maps /3rd Stage Maps Collected Villages	Status of Drones	additional drones require villages / drone/ day) to complete by 30th June, 2023
1.	Bilaspur	829	829	358	76	0	0	0	2	0
2.	Chamba	1069	1069	88	0	0	0	0	1	2
3.	Hamirpur	1505	1505	1505	1469	1028	354	119	0	0
4.	Kangra	3156	1011	274	0	0	0	0	1	9
5.	Kinnaur	157	157	36	26	0	0	0	0	1
6.	Kullu	378	190	4	0	0	0	0	0	1
7.	Lahual – Spiti	217	217	95	63	0	0	0	0	1
8.	Mandi	2574	2574	286	0	0	0	0	2	6
9.	Shimla	2036	2036	173	0	0	0	0	3	5
10.	Sirmaur	724	719	260	127	0	0	0	2	1
11.	Solan	2025	1905	613	0	0	0	0	2	2
12.	Una	526	524	405	192	0	0	0	0	1
	Total	**15196**	**12736**	**4097**	**1956**	**1028**	**354**	**119**	**13**	**29**

Way forward

• **बेहतर योजना:** सटीक भूमि रिकॉर्ड और जीआईएस मानचित्रों के निर्माण से पंचायतों को बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता मिलेगी।

• **भूमि राजस्व प्रबंधन:** इसके साथ, ग्राम पंचायतें राज्यों में अपनी संपत्ति कर निर्धारण और संग्रह को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकती हैं।

• **राजस्व सृजन:** इससे उनके स्वयं के राजस्व के स्रोत उत्पन्न होंगे जिनका उपयोग विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए लाभकारी रूप से किया जा सकता है।

• **ड्रोन उद्योग को बढ़ावा:** इस योजना ने देश में ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा दिया है।

निष्कर्ष:

स्वामित्व योजना मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण भूमि मालिकों को कानूनी संपत्ति अधिकार प्रदान करना है। इस योजना में ग्रामीण समुदायों की भूमि संपत्ति के आर्थिक मूल्य को अनलॉक करके उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार करने की क्षमता है। इस प्रकार, स्वामित्व योजना का लक्ष्य गांवों और उनके निवासियों के सशक्तिकरण के माध्यम से ग्राम पंचायत का समग्र विकास करना है जो अंततः ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा।

****

माननीय केंद्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने पंचायत विकास सूचकांक पर जारी की रिपोर्ट

28 जून, 2023 को पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) पर राष्ट्रीय कार्यशाला में केंद्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल द्वारा पंचायत विकास सूचकांक पर रिपोर्ट जारी की गई।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रधान सचिवों के साथ-साथ पंचायती राज, ग्रामीण विकास, योजना और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। साथ ही, सांख्यिकी और कार्यक्रम निगरानी, एसआईआरडी और पीआर के निदेशक, राज्य एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी और एसडीजी सेल के अधिकारी और अन्य प्रमुख हितधारकों ने पंचायत विकास सूचकांक पर राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य फोकस डेटा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए मंत्रालय के पोर्टल/डैशबोर्ड के एकीकरण पर रणनीतिक योजना और रोडमैप विकसित करना, पंचायत में एलएसडीजी के साथ संरेखण में योजनाबद्ध प्रगति का आकलन करना, विभिन्न मंत्रालय/विभाग, पंचायतें और ज्ञान भागीदारी और सक्रिय समर्थन के साथ पंचायत विकास सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र का आकलन करना था। राष्ट्रीय कार्यशाला को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और यह सभी स्तरों पर साक्ष्य आधारित विकास के लिए मजबूत तंत्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने में उल्लेखनीय रूप से प्रभावी साबित हुई।

प्रतिभागियों को अपने संबोधन में, श्री पाटिल ने रेखांकित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत केंद्र सरकार ने पिछले नौ वर्षों से अधिक समय के दौरान पंचायती राज संस्थानों (पीआरआईएस) को सर्वोत्तम तरीके से समर्थन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। पंचायती राज के मूल उद्देश्यों को सही मायने में प्राप्त किया जाए। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और विकासात्मक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के वित्तीय संसाधनों के आवंटन में काफी वृद्धि देखी है। पंचायत समर्थक पहलों की एक श्रृंखला ने एक नए युग की शुरुआत की है जिसमें पंचायतें अपने अनुसार कार्य कर सकती हैं।

राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि सभी हितधारकों के समर्थन के बिना गांवों का सर्वांगीण विकास और परिवर्तन संभव नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित समय सीमा के भीतर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए पंचायतों को लगातार प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक रूप से ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, समग्र विकास के मापदंडों पर पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को भी एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि सभी ग्राम पंचायतें मिलकर प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ें।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार ने पंचायत विकास सूचकांक पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए पंचायत विकास सूचकांक के माध्यम से सभी स्तरों पर साक्ष्य आधारित विकास लक्ष्यों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि पंचायत विकास सूचकांक विभिन्न चरणों का एक तार्किक संयोजन है। हम वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, यदि पंचायतें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्णय लेती हैं तो वे इसके लिए संसाधन खोजेंगी जिसके लिए पिछले डेढ़ साल में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं।

श्रीमती जयश्री रघुनंदन, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार एवं पीडीआई पर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है, डेटा संग्रह आसान और सरल होना चाहिए, और डेटा संग्रह के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है।

श्रीमती राधा आश्रित, डीडीजी, डीएमईओ, नीति आयोग एवं पीडीआई समिति के सदस्य, डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी, निदेशक, एसआईआरडी एवं पीआर, महाराष्ट्र, श्रीमती अदिति दास राउत, अतिरिक्त सचिव, महिला एवं जनसंपर्क मंत्रालय; बाल विकास, श्री अमित शुक्ला, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्री सुनील जैन, डीडीजी, एनआईसी, श्री वी हेज, डीडीजी, स्कूल शिक्षा एवं विभाग; साक्षरता, शिक्षा मंत्रालय, श्री समीर कुमार, आर्थिक सलाहकार, पेयजल एवं जल विभाग; स्वच्छता, जल शक्ति मंत्रालय, डॉ. गोविंद बंसल, निदेशक (मातृ स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य मंत्रालय; परिवार कल्याण, श्री राजेश गुप्ता, निदेशक, एनआईटीटी आयोग, डॉ. संजय कुमार, निदेशक, सांख्यिकी एवं मंत्रालय; कार्यक्रम कार्यान्वयन और भारत सरकार और राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार और अंतर्दृष्टि साझा की और राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान विचार-विमर्श को समृद्ध किया।

****

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सशक्त पंचायत सतत् विकास

G20 भारत 2023 INDIA

Ministry of Panchayati Raj

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj

www.youtube.com/channel/UCEVBqQXipAuDqZsinwto4nA

www.twitter.com/mopr_goi?ref_src=twsrc%5E-google%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

www.panchayat.gov.in/

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित
मुख्य संपादक:श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, टावर-2, नॉवा तल, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 द्वारा प्रकाशित